



प्रिलिम्स रिफ्रेशर प्रोग्राम 2020 : टेस्ट 10

1. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है।
2. इसमें अल्पकालिक बेरोज़गार व्यक्तियों, जो नए रोज़गार के तलाश में हों, को नकद सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948** के अंतर्गत शामिल बीमाकृत व्यक्तियों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)** का शुभारंभ किया है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- अल्पकालीन बेरोज़गारी की परिस्थिति में, नई नौकरी खोजने के दौरान अल्पकालिक बेरोज़गार सीधे अपने बैंक खाते में नकदी राहत प्राप्त करेंगे। **अल्पकालिक बेरोज़गार व्यक्तियों को दिया गया नकद लाभ उनकी 90 दिनों की औसत कमाई का 25% होगा। अतः कथन 2 सही है।**

2. निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक (HCI) जारी करता है?

- a. विश्व बैंक
- b. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- c. विश्व आर्थिक मंच
- d. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में 'मानव पूंजी सूचकांक'**

(HCI) जारी किया जाता है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

- विश्व विकास रिपोर्ट (WDR), 2019 की थीम 'द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क (The Changing Nature of Work)' है।
- HCI को 157 देशों के लिये तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य वर्तमान समय में पैदा हुए बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उसके द्वारा संभावित रूप से प्राप्त की जाने वाली मानव पूंजी की गणना करना है।
- **HCI में निम्न तीन घटक हैं:**
 - उत्तरजीविता (पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग की मृत्यु दर के आकलन पर आधारित)
 - गुणवत्ता-समायोजित स्कूल के अपेक्षित वर्ष, जो शिक्षा की मात्रा व गुणवत्ता पर आधारित है।
 - स्वास्थ्य वातावरण में दो कारकों का प्रयोग किया जाता है- (a) वयस्क उत्तरजीविता दर और (b) 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये स्टंटिंग।
- रिपोर्ट में भारत के लिये HCI के संबंध में महत्वपूर्ण अवलोकन निम्नानुसार हैं:
 - HCI-2018 में भारत 0.44 अंकों के साथ 115वें स्थान पर है।
 - आज भारत में पैदा होने वाला कोई बच्चा, पूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिलने की अवस्था में संभावित उत्पादक क्षमता की तुलना में केवल 44 प्रतिशत ही उत्पादक होगा।
 - भारत में महिलाओं के लिये HCI पुरुषों की अपेक्षा सीमांत रूप से बेहतर है।
 - पिछले पाँच वर्षों में भारत में HCI घटकों में सुधार हुआ है।

3. प्रधानमंत्री युवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:



1. यह योजना उद्यमिता आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये शुरू की गई है।
2. इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (MOOCs) को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

प्रधानमंत्री युवा योजना

- **प्रधानमंत्री युवा योजना** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की **उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर प्रमुख योजना** है।
- यह परियोजना पाँच साल (2016-17 से 2020-21) तक 499.94 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 वर्षों में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। **अतः कथन 1 सही है।**
- राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE), ने MSDE का हिस्सा बनने के बाद पूरे देश में नवोदित उद्यमियों के मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया है।
- प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में 2200 उच्च शिक्षण संस्थानों (कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और प्रमुख संस्थानों), 300 स्कूलों, 500 आई.टी.आई. और 50 उद्यमिता विकास केंद्रों को वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (MOOCs) के माध्यम से शामिल किया गया है। **अतः कथन 2 सही है।**
- इस योजना के तहत, सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) स्थानीय अधिकारियों और उद्योगों के साथ मिलकर रोज़गार

एकत्रीकरण की दिशा में काम करेगी। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों को इससे बाहर कर दिया जाएगा।

- यह योजना पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने उद्यमशीलता के क्षेत्र में सुधार करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये प्रेरित करेगी और उन लोगों को आगे और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये प्रेरित करेगी जो देश के उद्यमशील परिवेश का हिस्सा हैं।

4. PM-आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (PPPS) इसके प्रमुख घटकों में से एक है।
2. इस योजना के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से नैफेड एवं भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा दालों और कोपरा की वास्तविक खरीदारी की जाएगी।
3. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को 6000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2 और 3
- c. 1, 2 और 3
- d. केवल 1 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिये सितंबर 2018 में एक नई समग्र योजना '**प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा)** को मंजूरी दी गई थी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु इस की घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
- 'पीएम-आशा' के घटक निम्नलिखित हैं-
 - मूल्य समर्थन योजना (PSS)
 - मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS)



- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (PPPS)। अतः कथन 1 सही है।
 - मूल्य समर्थन योजना (PSS) में दालों, तिलहन और कोपरा की वास्तविक खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ की जाएगी। यह भी तय किया गया है कि नैफेड के अलावा, भारतीय खाद्य निगम (FCI) राज्यों/ज़िलों में PSS का संचालन करेगा।
 - खरीद में व्यय और खरीद की वजह से होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वहन किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
 - PDPS के तहत उन सभी तिलहनों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है, जिनके लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान अधिसूचित बाज़ार में उपज बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को किया जाएगा।
 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 में लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
 - इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
 - आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिये ही शुरू की गई थी, किंतु मई, 2019 को कैबिनेट द्वारा लिये गए निर्णय के बाद यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
5. 'भारत में पारदर्शिता के साथ कोयले के दोहन और आवंटन संबंधी योजना' (शक्ति) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. इसने विवेक के आधार कोयला लिंकेज के आवंटन की पूर्व प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है।
 2. यह शुल्क पर छूट के माध्यम से सस्ती बिजली प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- a. केवल 1
 - b. केवल 2
 - c. 1 और 2 दोनों
 - d. न तो 1 और न ही 2
- उत्तर: (c)
- व्याख्या:
- भारत में पारदर्शिता के साथ कोयले के दोहन और आवंटन संबंधी योजना (शक्ति)
- नीलामी या टैरिफ-आधारित बोली के आधार पर बिजली उत्पादकों को कोयला लिंकेज सुनिश्चित करने के लिये शक्ति योजना शुरू की गई है।
 - 'शक्ति' योजना शुरू होने से पहले ऊर्जा संयंत्र या तो ई-नीलामी के ज़रिये अधिसूचित कीमतों से अधिक प्रीमियम का भुगतान कर कोयला प्राप्त करते थे या इंडोनेशिया से आयातित कोयले पर निर्भर थे, जिनकी बढ़ती मांग या आपूर्ति बाधित होने के कारण कीमतों में वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ता था।
 - इस योजना ने विवेक के आधार पर कोयला लिंकेज के आवंटन से संबंधित पूर्व प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है, जिससे कोयला आवंटन में पारदर्शिता आएगी। अतः कथन 1 सही है।
 - इसने घाटे में चल रहे कई संयंत्रों के लिये कोयले तक पहुँच सुनिश्चित की है जिससे बैंकिंग क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था को भी मदद मिली है।
 - नए हस्ताक्षरित ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA) के तहत कार्यान्वित योजना और आपूर्ति शुरू करने के बाद, महँगे कोयले स्रोतों पर बिजली संयंत्रों की निर्भरता बहुत कम हो गई है, जिससे ईंधन की लागत में भी बचत हो रही है।



- यह टैरिफ/शुल्क पर छूट के आधार पर पारदर्शी बोली के माध्यम से किफायती बिजली उपलब्ध कराने में भी मदद करेगी।
अतः कथन 2 सही है।
 - यह योजना सरकार के 24x7 किफायती 'सभी के लिये बिजली' दृष्टिकोण को और सशक्त बनाएगी।
6. दीनदयाल स्पर्श योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इसे संचार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
 2. यह स्कूली बच्चों के लिये अखिल भारतीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है।
 3. इसका उद्देश्य छात्रों के मध्य डाक टिकट संग्रह को एक रूचि के रूप में बढ़ावा देना है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. 1, 2 और 3
- b. केवल 2 और 3
- c. केवल 3
- d. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- दीनदयाल स्पर्श (SPARSH) योजना की शुरुआत संचार मंत्रालय द्वारा की गई है। यहाँ 'स्पर्श' का पूरा नाम 'स्टार्ट-अप फॉर प्रमोशन ऑफ एंटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्पस एज़ ए हॉबी' (एक रूचि के रूप में टिकट में अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिये छात्रवृत्ति) है। **अतः कथन 1 सही है।**
- यह स्कूली बच्चों के लिये अखिल भारतीय स्तर पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को 6000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह को एक रूचि के रूप में चुना है। **अतः कथन 2 सही है।**
- इसका उद्देश्य छात्रों के बीच डाक टिकट संग्रह को एक रूचि के रूप में बढ़ावा देना है। **अतः कथन 3 सही है।**
 - डाक टिकट संग्रह (Philately) का तात्पर्य डाक टिकटों के संग्रहण और अध्ययन में रूचि से है। यह

टिकटों और अन्य डाक टिकट संबंधी उत्पादों के संग्रह, मूल्यांकन एवं अनुसंधान गतिविधियों को भी शामिल करता है।

7. अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
2. केवल वरिष्ठ नागरिक ही इसका लक्षित समूह हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
 - अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) के तहत वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। **अतः कथन 2 सही है।**
 - लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य राज्यों के सहयोग से बल्क ड्रग पार्क विकसित करना है।
 2. भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग चीन से बुनियादी कच्चे माल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
 3. फार्मास्युटिकल उद्योग में उपयोग होने वाले कच्चे माल को सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) कहा जाता है।



उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना (Promotion of Bulk Drug Parks scheme) के अंतर्गत तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य राज्यों के सहयोग से 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क का विकास करना है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग बुनियादी कच्चे माल के आयात पर अधिकाधिक निर्भर है। भारत का सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients- API) आयात लगभग 3.5 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का है जिसका लगभग 70% (2.5 बिलियन डॉलर) चीन से प्राप्त होता है। **अतः कथन 2 सही है।**
 - कच्चे माल से अभिप्राय उन रासायनिक यौगिकों से है जिनका उपयोग API निर्माण के लिये आधार के रूप में किया जाता है। APIs परिष्कृत फार्मास्युटिकल उत्पाद (FPP) में वांछित औषधीय सक्रियता प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का संयोजन है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
9. हाल ही में जारी "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के बारे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- COVID-19 से मुकाबला कर रहे प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
 - केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल लोगों को अगले तीन माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त गेहूं या चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
 - मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी दोगुनी कर दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 2
- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण पैकेज के तहत अगले तीन माह के लिये COVID-19 से मुकाबला कर रहे प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। **अतः कथन 1 सही है।**
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पहले से प्रदत्त 5 किलोग्राम सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के अतिरिक्त पाँच किलोग्राम गेहूं या चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। **अतः कथन 2 सही है।**
 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA) अधिनियम योजना के तहत मज़दूरी को 182 रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
10. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा वित्तपोषित हैं।
 - ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1998 में एकलव्य मॉडल आवासीय (EMR) विद्यालय



योजना शुरू की गई थी और इस तरह के प्रथम स्कूल का शुभारंभ वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRs) जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- इन स्कूलों में परीक्षाओं के नतीजे जनजातीय क्षेत्रों में मौजूद अन्य सरकारी विद्यालयों की तुलना में आम तौर पर बेहतर रहते हैं।
 - EMR स्कूलों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का औसत आँकड़ा 90% से भी अधिक है।
 - EMR स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
- EMRs केवल अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च विद्यालय शिक्षा पर केंद्रित हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- वर्ष 2010 के मौजूदा EMRS दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (ITDP) के तहत कम-से-कम एक EMR विद्यालय खोला जाएगा, जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी 50% है।

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाज़ार में तरलता को समायोजित करने के लिये सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के विक्रय व क्रय को खुला बाज़ार परिचालन कहा जाता है।
2. चलनिधि समायोजन सुविधा तरलता को स्थिर करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकल्पित एक मौद्रिक उपकरण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों

d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- RBI द्वारा खुला बाज़ार परिचालन किया जाता है। इसमें मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करने के लिये बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों (Govt- Securities) की बिक्री या खरीद शामिल होती है।
- जब RBI बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है तो वह बाज़ार से मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर, जब RBI बाज़ार से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है तो वह बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति शुरू करना चाहता है। अतः कथन 1 सही है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility-LAF) बाज़ार में तरलता को समायोजित या स्थिर करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया मौद्रिक उपकरण/उपाय है। रेपो (Repurchasing Option) और रिवर्स रेपो (Reverse Repurchasing Option) प्रक्रियाएँ LAF के दो प्रमुख घटक हैं।
- यह उपाय वाणिज्यिक बैंकों की तत्काल आवश्यकताओं की स्थिति में अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर RBI से अतिरिक्त ऋण लेने और बाज़ार में कम मांग होने पर RBI के पास अपने पैसे सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसलिये यह बाज़ार में मुद्रा की तरलता को स्थिर करता है। अतः कथन 2 सही है।

12. कर उत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह किसी फर्म द्वारा कर परिहार (Tax Avoidance) का एक अवैध तरीका है।
2. न्यूनतम कर व्यवस्था वाले देशों को 'टैक्स हैवन' के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)



व्याख्या:

कर उत्क्रमण (टैक्स इनवर्ज़न)

- यह कर संरचना की एक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब एक कंपनी अपना मुख्यालय निम्न कर वाले देश में स्थापित करती है जबकि अपने कार्यों संचालन उच्च कर वाले देशों (सामान्यतः उनके मूल देश) में करती है।
- इस तरह ये कंपनियाँ अपने कर भुगतान देयताओं में कटौती करती हैं। यह कर परिहार (Tax (a)voidance) का एक विधिक तरीका है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- अमेरिका में उच्च आयकरों के कारण अमेरिकी निकायों में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस स्थानांतरण को कर परिहार गतिविधि के रूप में भी देखा जा सकता है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNC) ऐसा करती रहती हैं। अमेरिकी-मूल की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वर्ष 1970 से 1980 के दशक में अपने मुख्यालय को अमरीका से UK में स्थानांतरित कर लिया था।
- विश्व के जिन देशों में कंपनियों के लिये बहुत निम्न कर व्यवस्था है, वे बड़ी कंपनियों के मुख्यालय के लिये अत्यधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आए हैं। बरमूडा, वर्जिन द्वीपसमूह आदि ऐसे ही कुछ देश हैं (जो 'टैक्स हैवेन' के नाम से जाने जाते हैं)। **अतः कथन 2 सही है।**

13. सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
2. इन बॉण्डों की गणना बैंकों के सांविधिक तरलता अनुपात में नहीं की जाती है।
3. व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों तथा धर्मार्थ संस्थानों सहित केवल भारतीय निवासी संस्थाएँ ही इन बॉण्डों को खरीद सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2
- c. केवल 1 और 3
- d. केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड (SGBs) वे सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो स्वर्ण के ग्राम मात्रा में नामित होती हैं। ये भौतिक स्वर्ण का विकल्प हैं।
 - इस योजना के तहत, निवेशकों को शेयर निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होगा और बॉण्ड को परिपक्वता तिथि पर नकद में विनियमित किया जाएगा। इसे भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - ये बॉण्ड बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे।

इन बॉण्डों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1.	पात्रता	व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों तथा चैरिटेबल संस्थानों सहित केवल भारतीय निवासी संस्थाएँ ही इन बॉण्ड्स में निवेश हेतु पात्र है। अतः कथन 3 सही है।
2.	मूल्यवर्ग	बॉण्ड को 1 ग्राम की मूल इकाई के साथ स्वर्ण के ग्राम के गुणकों में नामित किया जाएगा।
3.	अवधि	इन बॉण्ड्स की अवधि 8 वर्ष है, ब्याज भुगतान तिथि 5वें, 6वें और 7वें वर्ष में निकास विकल्प के साथ उपलब्ध है।



4.	न्यूनतम सीमा	न्यूनतम स्वीकार्य निवेश 1 ग्राम स्वर्ण की होगी।
5.	अधिकतम सीमा	व्यक्तियों के लिये अभिदत्त की अधिकतम सीमा 4 किलो है, HUF के लिये 4 किलो और ट्रस्ट के लिये 20 किलो है।
6.	संयुक्त धारक	संयुक्त स्वामित्व की अवस्था में, 4 किलो की निवेश सीमा केवल पहले आवेदक पर लागू की जाएगी।
7.	भुगतान विकल्प	बॉण्ड के लिये भुगतान नकदी (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या डिमांड ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
8.	SLR योग्यता	इनका प्रयोग वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने में भी किया जा सकेगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- वेबलेन वस्तुओं का माँग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है।
- वेबलेन वस्तुएँ सामान्यतः हीन उत्पाद (Inferior Products) होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

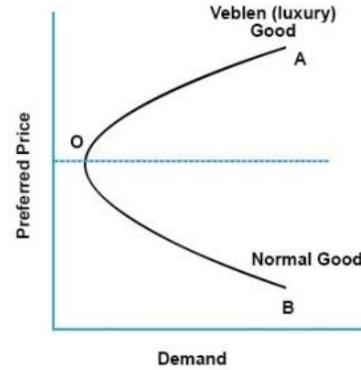
व्याख्या:

वेबलेन प्रभाव

- इसका नाम अमरीकी अर्थशास्त्री टॉरस्टेन बुंडे वेबलेन (1857-1929) के नाम पर रखा गया है। यह उपभोग का एक सिद्धांत है जो बताता है कि उपभोक्ताओं में 'अद्योमुखी ढलान माँग वक्र' के विपरीत 'उर्ध्वमुखी

ढलान माँग वक्र' पाया जा सकता है। **अतः कथन 1 सही है।**

- ऐसा इसलिये होता है क्योंकि उनमें प्रदर्शन उपभोग की प्रवृत्ति होती है (अद्योमुखी ढलान माँग वक्र का अर्थ है कि माँग की मात्रा मूल्य के विपरीत बदलती रहती है, अर्थात् मूल्य वृद्धि के साथ माँग घटती है)।



- संकल्पना:** यह सिद्धांत बताता है कि किसी विशेष वस्तु की माँग की गई मात्रा मूल्य में बदलाव के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदल सकती है (अर्थात्, जैसे ही मूल्य वृद्धि होती है, माँग में भी वृद्धि होने लगती है)।

वेबलेन वस्तु

- वेबलेन वस्तु ऐसी वस्तु है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ माँग वृद्धि की प्रवृत्ति होती है और अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण ये प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है।
- वेबलेन वस्तु का 'माँग वक्र' ऊपर की ओर झुका होता है जो सामान्य 'अद्योमुखी ढलान माँग वक्र' के विपरीत संचालित होता है।
- यद्यपि, वेबलेन वस्तु सामान्यतः उच्च गुणवत्तायुक्त प्रतिष्ठित उत्पाद होती है और यह गिफिन वस्तु जो ऐसे गौण उत्पाद हैं जिनके विकल्प सरलता से उपलब्ध नहीं होते से विपरीत स्थिति है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

15. 'वैध मुद्रा' (Legal Tender) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- यह मौद्रिक प्राधिकरण या सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है और इसे किसी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।



2. भारत में सिक्के सीमित वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- मौद्रिक प्राधिकरण या सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, उसे वैध मुद्रा कहा जाता है।
अतः कथन 1 सही है।
- यह वह धन है जिसे कानून का समर्थन प्राप्त है, साथ ही यह ऋण के भुगतान के लिये वैध माना जाता है। इसे ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। RBI अधिनियम, 1934 जो केंद्रीय बैंक को बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देता है, के अनुसार 'प्रत्येक बैंक नोट को इसमें दी गई राशि के भुगतान के लिये भारत में किसी भी स्थान पर वैध मुद्रा माना जाएगा'।
- ये प्रकृति में सीमित या असीमित हो सकते हैं। भारत में, सिक्के सीमित वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। जैसे 10 रुपए तक के बकाए के लिये 50 पैसे के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में पेश किया जा सकता है।
अतः कथन 2 सही है।
- करेंसी नोट असीमित वैध मुद्रा हैं और इन्हें कितने भी बकाया राशि के भुगतान के रूप में पेश किया जा सकता है।

नोट: सरकार करेंसी नोट की असीमित प्रकृति पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे बजट 2017 के, वित्त विधेयक का खंड 269ST 2 लाख रुपए और उससे अधिक के नकद लेन-देन को प्रतिबंधित करता है।

16. हाल ही में समाचारों में देखा गया 'ऑपरेशन नमस्ते' किससे संबंधित है?

- भारतीय सेना का COVID-19 अभियान
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर भारत-चीन का संयुक्त समझौता
- इटली में भेजा गया भारत का सहायता मिशन

d. विदेशी देशों से भारतीयों को बाहर निकालने से
उत्तर: (a)

व्याख्या:

- ऑपरेशन नमस्ते (Operation Namaste) भारतीय सेना का COVID-19 अभियान है जो महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करता है।
अतः विकल्प (a) सही है।

17. अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों से जुड़े शब्द 'अर्-रिनाम', 'मोटर', 'अरुए' निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

- चावल की खेती की स्वदेशी विधि से।
- शस्योत्सव से।
- पवित्र उपवन में धार्मिक कार्य से।
- संगरोध प्रक्रियाओं से।

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- अर्-रिनाम (Arr-Rinam), मोटर (Motor), अरुए (Arrue) अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समुदायों द्वारा किये गए संगरोध अनुष्ठानों (Quarantine Rituals) को संदर्भित करते हैं।
- गालोस (Galos) अर्-रिनाम अनुष्ठान करते हैं। मोटर या पॉटर (Pator) प्रणाली एदि समुदाय (Adi Community) और अरुए न्याशी (Nyishi) समुदाय से संबंधित है।
अतः विकल्प (d) सही है।

18. हाल ही में समाचारों में देखा गया MACS 4028 है:

- रूस से आयातित एक लड़ाकू विमान
- चंद्रयान -2 के लिये रोवर
- गेहूँ की एक बायोफोर्टिफाइड किस्म
- COVID-19 परीक्षण किट

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- MACS 4028 एक ड्यूम गेहूँ की बायोफोर्टिफाइड किस्म है जिसे अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (Agharkar Research Institute- ARI), पुणे के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इस नई गेहूँ की किस्म में 14.7% प्रोटीन, 40.3 ppm जिंक, 46.1



ppm लोहे की मात्रा पाई जाती है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

19. 'सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग एक नैनोस्तरीय आकार की परत है।
 2. एक सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग से सतही जल के प्रति एक विकर्षक परत बनती है।
 3. कमल के पत्ते में सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग पाई जाती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1
- b. केवल 1 और 2
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- हाइड्रोफोबिसिटी शब्द दो ग्रीक शब्दों- हाइड्रो (जल) और फोबोस (भय/डर) से मिलकर बना है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है जल के लिये प्रतिकर्षण (Repulsion) का गुण रखने वाला है।
- सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग एक नैनोस्तरीय सतही परत है जो जल के प्रति विकर्षक गुण रखती है। अतः कथन 1 सही है।
 - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) धनबाद के 'इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स' (ISM) तथा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (Ohio State University) की टीम ने पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो कणों का इस्तेमाल कर कोटिंग में प्रयुक्त होने वाले सुपरहाइड्रोफोबिक पदार्थ का निर्माण किया है।
 - कोटिंग की इस तकनीक में सुपरहाइड्रोफोबिक (सतह पर न चिपकने की प्रवृत्ति) गुण पाया गया। इस कोटिंग तकनीक को अम्लीय (pH5) और क्षारीय (pH8) दोनों स्थितियों में छह सप्ताह से अधिक

समय तथा 230°C तापमान तक तक टिकाऊ पाया गया।

- सुपरहाइड्रोफोबिक कोटिंग से कोई सतह जल विकर्षक बन जाती है। **अतः कथन 2 सही है।**
- सुपर-हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स प्रकृति में भी पाए जाते हैं जो पौधे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जैसे कि कमल का पत्ती और कुछ कीटों के पंख। **अतः कथन 3 सही है।**
 - कोटिंग द्वारा प्रदर्शित एक अन्य क्षमता; स्व-सफाई का कार्य है। पानी की बूँदें तथा धूल कोटिंग सतह से चिपकती नहीं हैं तथा स्वतः सतह से लुढ़क जाती हैं।

20. दीक्षा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. पोर्टल को केवल सरकारी संगठनों की पहल में एकीकृत किया जा सकता है।
3. यह डिग्री स्तर पूर्व के पाठ्यक्रमों के साथ पंजीकृत शिक्षार्थियों की जाँच और प्रमाणन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2 और 3
- c. केवल 1 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

दीक्षा पोर्टल (DIKSHA Portal)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा शिक्षकों के लिये ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (**Digital Infrastructure for Knowledge Sharing-DIKSHA**) अर्थात् दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। **अतः कथन 1 सही है।**
- राज्य, सरकारी निकाय और यहां तक कि निजी संगठन भी अपने संबंधित शिक्षक पहल को दीक्षा पोर्टल में एकीकृत कर सकते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**



- दीक्षा पोर्टल की शुरुआत शिक्षक समुदाय को समाचार, किसी प्रकार की घोषणा, आकलन तथा शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिये की गई है जो शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।
- यह शिक्षकों को एक डिजिटल मंच प्रदान करता है जो उन्हें सीखने और स्वयं को प्रशिक्षित करने तथा शिक्षक समुदाय के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह डिग्री पूर्व स्तर के पाठ्यक्रमों के साथ पंजीकृत शिक्षार्थियों की जांच और प्रमाणन नहीं करता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
- यह पोर्टल नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के बाद, NCERT पाठ्यपुस्तकों और पाठों (lessons) तक पहुँच प्रदान करता है।

21. केंद्र सरकार की कुल देनदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इन देनदारियों में सार्वजनिक ऋण और लोक खाता संबंधी देयताएँ दोनों शामिल हैं।
2. FRBM अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद GDP के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में निरंतर कमी आ रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

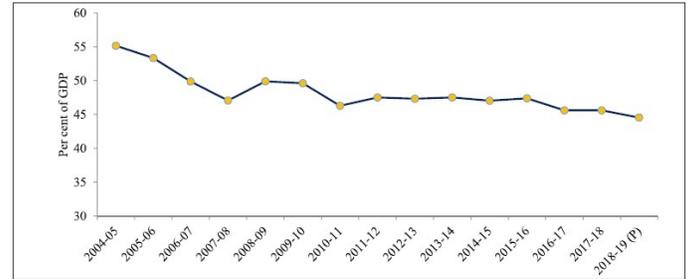
व्याख्या:

- केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में सार्वजनिक ऋण के साथ-साथ लोक खाते संबंधी देयताएँ भी शामिल होती हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
 - लोक खाता भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर अनुबंधित ऋण है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक और बाह्य ऋण दोनों शामिल है।

- लोक खाता संबंधी देयता में ऐसे लेन-देन शामिल है जहाँ सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य कर रही है। उदाहरणस्वरूप, **भविष्य निधि, लघु बचत** आदि। ये धनराशि सरकार की नहीं है। कुछ समय पश्चात् इसके वास्तविक स्वामियों को इस राशि का पुनः भुगतान करना होता है।

- FRBM अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देनदारियों (जिसे ऋण-GDP अनुपात भी कहा जाता है) में निरंतर कमी आई है।

- यह दोनों राजकोषीय समेकन प्रयासों के साथ-साथ अपेक्षाकृत GDP की उच्च वृद्धि का परिणाम है। **अतः कथन 2 सही है।**



Source: Various issues of Status Paper on Government Debt; P: Provisional

चित्र: केंद्र के ऋण-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति

22. क्रांति तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस मिशन को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
2. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु मौलिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास, नवाचारों और स्टार्ट-अप पर ध्यान दिया जाएगा।
3. अत्यधिक जटिल समस्याओं के इंजीनियरिंग समाधानों के लिये क्रांति यात्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?



- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारत सरकार ने बजट- 2020 में **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा लागू** किये जाने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिये 8000 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ **क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Quantum Technologies & Applications-NM-QTA)** की घोषणा की है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- इस मिशन का फोकस मौलिक विज्ञान, अनुवाद, प्रौद्योगिकी विकास, मानवीय एवं अवसंरचना संसाधन उत्पादन, नवाचार और स्टार्ट-अप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दों पर होगा। **अतः कथन 2 सही है।**
- कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन, रसायन विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग और यांत्रिकी में बेहद जटिल समस्याओं के अभियान्तिकी समाधान के लिये क्वांटम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा। **अतः कथन 3 सही है।**
- इस मिशन की कुछ अन्य विशेषताएँ नीचे दिये गए इंफोग्राफिक में उल्लिखित हैं-



केन्द्रीय बजट
UNION BUDGET 2020

Budget 2020 announced Rs 8,000 crore over the next 5-yr
National Mission on Quantum technology and its applica

- The areas of focus for the NM-QTA Mission will be in fundamental science, translation, technology development and towards addressing issues concerning national priorities
- The mission can help prepare next generation skilled manpower, boost translational research and also encourage entrepreneurship and start-up ecosystem development.
- Quantum principles will be used for engineering solutions to extremely complex problems in computing, communications, sensing, chemistry, cryptography, imaging and mechanics
- Their applications which will be boosted incld aero-space engineering, numerical weather simulations, securing the communications & transactions, cyber security, advanced manu health, agriculture, education
- It can bring India in the list of few countries v in this emerging field will have a greater adv, garnering multifold economic growth and dor leadership role

IndiaDST www.dst.gov.in

23. स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है:

- जनहित सुनिश्चित करने हेतु
- नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु
- संपदा के समतापूर्ण वितरण हेतु
- एकाधिकार का दुरुपयोग रोकने हेतु
- संसाधनों का दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1, 2 और 5
- केवल 1, 3 और 4
- केवल 1, 2, 3 और 4
- 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों को आवंटित करने में प्रभावशाली होते हैं।
- हालाँकि सरकारें उन स्थितियों में हस्तक्षेप करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जहाँ 'बाज़ार की विफलताएँ' अत्यधिक हैं।
 - 'बाज़ार की विफलताएँ' ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ संसाधन आवंटित करने में बाज़ार सक्षम नहीं हो पाते और वे इसमें विफल रहते हैं।
- एक स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार की क्षमताओं और कमज़ोरियों को निम्नलिखित चित्र से देखा जा सकता है:



- आवश्यक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार जनहित एवं संपदा का समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने और एकाधिकार के दुरुपयोग को



रोक पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

- परंतु बाज़ार नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है तथा संसाधनों के कुशल और दक्ष उपयोग को सुनिश्चित कर सकता है और यहाँ सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

24 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित

1. एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियाँ अधिनियम, 1969	प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002
2. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
3. रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985	कंपनी अधिनियम 2013

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

• **एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियाँ (MRTP) अधिनियम, 1969:**

- इस अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की रोकथाम, एकाधिकार को नियंत्रित करना, एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को निषेधित करना है। इसने कंपनियों को वैश्विक स्तर तक वृद्धि करने और बड़ा आकार प्राप्त करने के मार्ग को बाधित किया और लघु स्तरीय कंपनियों के प्रसार को प्रेरित किया।

- **प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 ने MRTP अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।** प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम का उद्देश्य 'बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाज़ारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किये जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और वर्चस्वकारी स्थिति के दुरुपयोग को रोकना है।' इसका उद्देश्य 'वर्चस्व की रोकथाम' के बजाय 'वर्चस्व के दुरुपयोग को विनियमित करना है। **अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।**

• **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973:**

- कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा होने और इससे अधिक हिस्सेदारी के लिये RBI से अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। इससे विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच सीमित हो गई।

- बाह्य व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्ष 1999 में इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) द्वारा निरस्त एवं प्रतिस्थापित किया गया। फेरा के तहत, जब तक विशेष अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक सब कुछ निषिद्ध था, जबकि फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाज़ार के विकास को सक्षम करने के लिये विशेष रूप से प्रतिबंधित या विनियमित होने तक अनुमति दी गई थी। **अतः युग्म 2 सही सुमेलित है।**

• **रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (SICA), 1985:**

- रुग्ण और संभाव्य रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाना तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन



बोर्ड (BIFR) द्वारा निवारक, सुधारक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का तेज़ी से निर्धारण करना इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य थे। यह अधिनियम देनदार-अनुकूल (Debtor-Friendly) था और मूल्यवान परिसंपत्ति पार नियंत्रण बनाए रखते थे।

- SICA अधिनियम को 1 जनवरी 2004 को निरस्त कर दिया गया और दिवालिया एवं दिवालियापन कोड (IBC), 2016 का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 1 दिसंबर, 2016 को BIFR को विघटित कर दिया गया था। अतः युग्म 3 सही सुमेहित नहीं है।

25. भारत के निम्नलिखित व्यापारिक भागीदारों को व्यापार की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिये:

1. चीन
2. संयुक्त राज्य अमेरिका
3. सऊदी अरब
4. संयुक्त अरब अमीरात

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

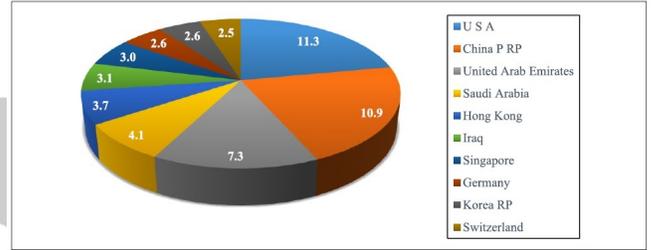
- a. 1-2-3-4
- b. 2-1-4-3
- c. 1-2-4-3
- d. 2-1-3-4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वर्ष 2019-20 के दौरान भारत के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों का संयुक्त रूप से भारत के कुल व्यापारिक व्यापार में 50% से अधिक योगदान है।
- भारत के शीर्ष पाँच व्यापारिक भागीदार **USA > चीन > संयुक्त अरब अमीरात > सऊदी अरब > हॉन्गकॉन्ग** हैं। अतः विकल्प (b) सही है।
- दो शीर्ष व्यापारिक देश - USA और संयुक्त अरब अमीरात के साथ वर्ष 2014-15 से भारत का लगातार व्यापार अधिशेष रहा है।

- दूसरी ओर वर्ष 2014-15 से लगातार भारत का अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदारों जैसे- चीन, सऊदी अरब, इराक, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ व्यापारिक घाटा रहा है।
- इसके अलावा वर्ष 2018-19 में व्यापार घाटे में परिवर्तित होने से पहले वर्ष 2017-18 तक भारत का हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर के साथ व्यापार अधिशेष रहा था।



26. वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार निम्नलिखित सब्सिडी व्ययों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिये:

1. खाद्य सब्सिडी
2. उर्वरक सब्सिडी
3. विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये ब्याज सब्सिडी
4. पेट्रोलियम सब्सिडी

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. 1-2-3-4
- b. 4-1-2-3
- c. 1-2-4-3
- d. 4-3-2-1

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- केंद्रीय बजट 2020-21 में सब्सिडी पर कुल व्यय में वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान से 0.5% की कमी देखी गई। यह काफी सीमा तक उर्वरक सब्सिडी पर व्यय में कमी के कारण है।
 - **खाद्य सब्सिडी:** वर्ष 2020-21 में खाद्य सब्सिडी हेतु आवंटन 1,15,570 करोड़ रुपए है।
 - **उर्वरक सब्सिडी:** वर्ष 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 71,309 करोड़ रुपए है।



- **पेट्रोलियम सब्सिडी:** वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर व्यय 6.1 फीसदी बढ़कर 40,915 करोड़ रुपए है। पेट्रोलियम सब्सिडी में LPG और केरोसिन पर सब्सिडी भी शामिल है।
 - **अन्य सब्सिडी:** अन्य सब्सिडियों के व्यय में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये ब्याज सब्सिडी, कृषि उपज के मूल्य समर्थन योजना के लिये सब्सिडी एवं सरकारी खरीद के लिये राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता शामिल हैं।
 - इस प्रकार सब्सिडियों का सही अवरोही क्रम है-
 - **खाद्य > उर्वरक > पेट्रोलियम > विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये ब्याज अनुदान** है। अतः विकल्प (c) सही है।
27. निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (NIIP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. इसे किसी विशिष्ट समय बिंदु पर शेष विश्व के साथ किसी राष्ट्र के तुलन-पत्र के रूप में देखा जाता है।
 2. वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-2020 में भारत के NIIP के GDP से अनुपात में कमी आई है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- a. केवल 1
 - b. केवल 2
 - c. 1 और 2 दोनों
 - d. न तो 1 और न ही 2
- उत्तर: (a)**
व्याख्या:
- निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (NIIP) को किसी विशिष्ट समय बिंदु पर विश्व के शेष हिस्सों के साथ एक राष्ट्र के तुलन-पत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
 - यह एक विशिष्ट समय बिंदु पर किसी राष्ट्र के विदेशी परिसंपत्ति के स्टॉक और उस देश की परिसंपत्ति के विदेशी स्टॉक के बीच अंतर को मापता है। अतः कथन 1 सही है।
 - **NIIP:** GDP अनुपात में परिवर्तन एक देश द्वारा विदेशों में की गई बाह्य देनदारियों से देश द्वारा किये गए निवेश के प्रभाव को दर्शाता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में ऋण एवं इक्विटी सर्विसिंग भार में होने वाले निवल परिवर्तन को मापा जाता है।
 - वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-2020 में GDP से अनुपात के संदर्भ में भारत का निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (NIIP) बढ़ गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. बीमा घनत्व का मापन बीमा प्रीमियम को GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर किया जाता है।
 2. बीमा प्रवेशन की गणना जनसंख्या और प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- a. केवल 1
 - b. केवल 2
 - c. 1 और 2 दोनों
 - d. न तो 1 और न ही 2
- उत्तर: (d)**
व्याख्या:
- बीमा घनत्व (Insurance Density) और बीमा प्रवेशन (Insurance Penetration) का माप किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को इंगित करता है।
 - बीमा प्रवेशन GDP के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम अर्थात् यह भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - बीमा घनत्व की गणना बीमा प्रीमियम के जनसंख्या से अनुपात अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रीमियम के रूप में की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
29. सूक्ष्म वित्तीयन संस्थाओं (MFI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:



1. इनका उद्देश्य समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन है।
2. MFI द्वारा दिये गए ऋणों का आधे से अधिक भाग महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों को प्राप्त होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (Microfinance Institutions-MFI) की शुरुआत गैर-लाभकारी संस्थानों के रूप में हुई। इनका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - हालाँकि हाल ही में MFI सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही वित्तीय लाभ के लक्ष्य पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
 - अच्छे वित्तीय लाभ के साथ ही पदसोपानात्मक व्यवस्था के आधारभूत अर्थात् सबसे निम्नतम वर्ग पर सामाजिक प्रभाव डालने पर भी जोर दिया जा रहा है।
- वर्ष 2016 तक लगभग 97% ऋणकर्ता महिलाएँ और अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित थे। यह दर्शाता है कि इन MFI द्वारा दिये गए ऋण मुख्य रूप से समाज के सीमांत वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**

30. 'वर्ल्ड कमर्शियल एक्सपोर्ट्स' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वर्ष 2012-2018 के दौरान वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की तुलना में वस्तुओं के निर्यात में तेज़ी से वृद्धि हुई।

2. विश्व की वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले एक दशक से लगातार बढ़ी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- आर्थिक गतिविधियों में सेवाओं की बढ़ती भूमिका वैश्विक व्यापार और भारत के व्यापार में सेवाओं के बढ़ते महत्त्व से भी स्पष्ट होती है। दो समयावधियों- वर्ष 2005-11 और वर्ष 2012-2018 को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात एवं वस्तुओं के निर्यात की गति दोनों हाल के वर्षों में भारत और वैश्विक स्तर पर मंद हो गई है।
 - हालाँकि वर्ष 2005-11 के दौरान वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की तुलना में व्यापारिक निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था, परंतु बाद के वर्षों में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात ने वस्तुओं के निर्यात की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
 - इससे भारत और वैश्विक स्तर पर कुल निर्यात में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भागीदारी बढ़ी है।
 - विश्व व्यापार संगठन के आँकड़ों के अनुसार, विश्व के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की भागीदारी पिछले एक दशक में तेज़ी से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.5% तक पहुँच गई है, जो वस्तु निर्यातों के 1.7% से दोगुनी है। भारत अब विश्व के शीर्ष वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यातकों में 8वें स्थान पर है। **अतः कथन 2 सही है।**
31. 'लाभ के पद' की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. 'लाभ के पद' को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।



2. लाभ के पद के अंतर्गत अयोग्यता सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों चाहे वे संसद, विधानसभाओं या पंचायतों और नगर पालिकाओं के सदस्य हों, पर लागू होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- 'लाभ के पद' (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) शब्दावली को संविधान या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- संविधान के **अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1)(a)** में केवल यह कहा गया है कि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के लाभ का पद धारण करने पर निषेध है क्योंकि यह उन्हें आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाने की स्थिति में रख सकता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- जया बच्चन बनाम भारत संघ मामले (2006)** में सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ या आर्थिक लाभ प्रदान करने में सक्षम किसी भी पद को 'लाभ के पद' के रूप में परिभाषित किया।
- बाद में **स्वप्न रॉय मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी पद को लाभ का पद मानने हेतु परीक्षण के लिये निम्नलिखित मापदंडों का निर्धारण किया:
 - नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है अथवा नहीं।
 - सरकार के पास अपदस्थ करने या हटाने की शक्ति है या नहीं।
 - सरकार पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है अथवा नहीं।
 - सरकार ऐसे पदों के कार्यों को निर्धारित अथवा नियंत्रित करती है अथवा नहीं।

- कृत्य सरकार के लिये निष्पादित किये जाते हैं अथवा नहीं।

32. गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यह गृह मंत्रालय के अधीन एक अन्वेषण संस्था है।
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है।
- यह केवल केंद्र सरकार के विभागों से संबंधित मामलों की जाँच कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- केवल 2
- केवल 1 और 3
- केवल 1 और 2
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office-SFIO) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तहत एक **बहु-अनुशासनात्मक संगठन** (Multi-Disciplinary Organization) है, इसमें सफेदपोश अपराधों/धोखाधड़ी का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने अथवा इस संदर्भ में संस्तुति करने के लिये अकाउंटेंसी/लेखाकर्म (Accountancy), फॉरेंसिक ऑडिटिंग (Forensic Auditing), कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), जाँच (Investigation), कंपनी कानून (Company Law), पूंजी बाज़ार (Capital Market) और कराधान (Taxation) के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
 - इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2013 में SFIO के अधिकारियों को जाँच कार्यों में सहायता और सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड डेटा माइनिंग लेबोरेटरी (Computer Forensic and



Data Mining Laboratory-
CFDML) की स्थापना की गई।

- भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) की स्थापना की गई। उस समय SFIO को औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के अंतर्गत SFIO को वैधानिक दर्जा दिया गया है। **अतः कथन 2 सही है।**
 - SFIO में कंपनी कानून (Company Law) के उल्लंघन के संदर्भ में लोगों को गिरफ्तार करने की शक्तियाँ भी निहित हैं।
 - केंद्र सरकार द्वारा एक कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी की जाँच की शुरुआत की जा सकती है और निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय को यह कार्य सौंपा जा सकता है:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर।
 - एक कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव की सूचना पर, कि उसके मामलों की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।
 - जनहित में।
 - केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अनुरोध पर। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
33. संसद और राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिये होने वाले उप-चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर रिक्तियों को भरना होगा बशर्ते कि रिक्ति के संबंध में सदस्य का शेष कार्यकाल दो वर्ष या उससे अधिक हो।
 2. संसद के लिये उप-चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा और राज्य विधानसभाओं के लिये उप-चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A उस समय सीमा से संबंधित है जिसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा उपचुनावों के माध्यम से भरा जाना चाहिये。
 - संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिये ये चुनाव भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कराए जाते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- अधिनियम की यह धारा चुनाव/निर्वाचन आयोग को रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से 6 माह के भीतर रिक्तियों को भरने के लिये निर्देशित करती है बशर्ते **रिक्ति के संबंध में सदस्य शेष कार्यकाल एक वर्ष या उससे अधिक समय का हो। अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- **धारा 151A में अपवाद:** यदि केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव आयोग यह प्रमाणित करता है कि निर्धारित अवधि के भीतर उपचुनाव कराना कठिन है, तो धारा 151A को निष्प्रभावी किया जा सकता है।

34. निम्नलिखित में से कौन वयस्क शिक्षा और कौशल विकास में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन एवं कार्यान्वयन संगठन है?

- a. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण (NLMA)
- b. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
- c. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF)
- d. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या:



- वयस्क शिक्षा में सुधार के लिये, वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) को 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों के लिये शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को वर्ष 2009 में साक्षर भारत के रूप में आजीवन सीखने के नए प्रतिमानों के साथ संरक्षित किया गया था।
- **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (NLMA)** वयस्क शिक्षा और कौशल विकास में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन और कार्यान्वयन संगठन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान से ही, NLMA साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाने और लैंगिक अंतराल को 10% से कम करने का प्रयास कर रहा है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के राष्ट्रपति पर साबित दुर्व्यवहार के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
2. भारतीय राष्ट्रपति पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग लगाया जा सकता है।
3. भारतीय संसद के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2
- c. केवल 3
- d. केवल 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारत में संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया 'संविधान के उल्लंघन' के आधार पर प्रारंभ की जा सकती है। हालाँकि संविधान में 'संविधान का उल्लंघन' वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में देशद्रोह, रिश्वत और दुराचार जैसे मामलों के आधार पर संसद के प्रतिनिधि सदन द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की

जाती है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- भारत में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव पर कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, वहीं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के 51% सदस्यों की सहमति पर ही महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- भारतीय राष्ट्रपति को सदन की **कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से** महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर हटाया जाता है, **न कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा। अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- महाभियोग संसद की एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। **अतः कथन 3 सही है।**
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालाँकि वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

36. किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने के लिये एक विशेष अदालत में आवेदन किया जाता है। इस विशेष अदालत को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नामित किया जाता है?

- a. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
- b. बेनामी संपत्ति लेन-देन अधिनियम, 1988
- c. कंपनी अधिनियम, 2013
- d. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender-FEO) घोषित करने की अनुमति देता है, यदि:
 - उसके खिलाफ किसी निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तारी



वारंट जारी किया गया है और यह अपराध 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाला है, और

- उसने देश छोड़ दिया है और मुकदमे का सामना करने के लिये देश लौटने से इनकार कर दिया है।

- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिये विशेष अदालत (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नामित) में आवेदन किया जाएगा जिसमें ज़ब्त की जाने वाली संपत्तियों का विवरण और उस व्यक्ति के ठिकानों की सूचना होगी। **अतः विकल्प (a) सही है।**

- विशेष अदालत द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि नोटिस मिलने के कम-से-कम छह हफ्ते के भीतर वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर पेश हो। उस व्यक्ति के पेश होने पर विशेष अदालत द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ खारिज कर दी जाएंगी।

37. 'अस्ताना घोषणा' किससे संबंधित है?

- a. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से
- b. शिक्षा से
- c. आपदा प्रबंधन से
- d. साइबर सुरक्षा से

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- अक्टूबर 2018 में कज़ाकिस्तान के अस्ताना शहर में आयोजित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन ने दुनिया भर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देते हुए एक नई घोषणा का समर्थन किया। इस घोषणा में भारत सहित WHO के सभी 194 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए। **अतः विकल्प (a) सही है।**

- घोषणा का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर किये गए प्रयासों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई स्वास्थ्य के उच्चतम संभव प्राप्य मानक का आनंद लेने में सक्षम हो।

38. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला 'डेंगवैक्सिया' (Dengvaxia) शब्द किससे संबंधित है?

- a. किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकी का अध्ययन करने हेतु एक उपकरण से
- b. सौर प्रणाली से परे खोजे गए एक नए ग्रह से।
- c. USA में विनियामक सहमति प्राप्त करने वाले डेंगू के पहले टीके से।
- d. सुरक्षित बैंकिंग सुविधाओं के लिये विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन से।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- हाल ही में सनोफी पाश्चर (Sanofi Pasteur) के विवादास्पद वैक्सीन डेंगवैक्सिया (Dengvaxia) को US खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US-FDA) द्वारा मंजूरी दी गई है, लेकिन साथ ही इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

- ध्यातव्य है कि डेंगवैक्सिया, USA में विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रयोग हेतु सहमति प्राप्त करने वाला पहला डेंगू वैक्सीन है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

- डेंगवैक्सिया मूल रूप से एक जीवित और दुर्बलीकृत डेंगू विषाणु है।

- दुर्बलीकृत विषाणु एक ऐसा विषाणु होता है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के अपने गुणों को बनाए रखता है।

39. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला 'मावेली' शब्द किसे संदर्भित करता है?

- a. तमिलनाडु का फसल उत्सव
- b. साइबर हमलों से निपटने हेतु एक सॉफ्टवेयर टूल
- c. अंडमान और निकोबार की स्वदेशी जनजाति।
- d. केरल में पाई गई मेंढक की एक स्थानिक प्रजाति।

उत्तर: (d)

व्याख्या:



- महाबली या मावेली, एक पौराणिक राजा थे, जिन्होंने केरल के क्षेत्र पर शासन किया था। इन्हीं के नाम पर **केरल में पाए गए बैंगनी रंग के इस मेंढक को मावेली नाम दिया गया है।**
 - यह लगभग अपना पूरा जीवन भूमिगत सुरंगों में रहता है, एक वर्ष में एक ही दिन के लिये सतह पर निकलता है और अंडे देने के बाद पुनः पृथ्वी की सबसे गहरी परतों में लौट जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में संकटग्रस्त (Endangered) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। **अतः विकल्प (d) सही है।**
40. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प हाल ही में समाचारों में देखे गए 'IndAS' शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
- a. यह ISRO के संचार उपग्रहों की एक नवीन शृंखला है।
 - b. यह स्वदेशी रूप से विकसित एक सतह से सतह मारक क्षमता वाली मिसाइल प्रणाली है।
 - c. यह लेखांकन मानकों का एक समूह है जो वित्तीय लेन-देन के लेखांकन और रिपोर्टिंग को नियंत्रित करता है।
 - d. यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक नौ-सैन्य अभ्यास है।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारतीय लेखा मानक (Indian Accounting Standards-Ind AS) लेखांकन मानकों का समूह है जो वित्तीय लेन-देनों के लेखांकन और अभिलेखों के साथ ही लाभ-हानि खाते एवं कंपनी के तुलन पत्र जैसे विवरणों की प्रस्तुति को नियंत्रित करते हैं। **अतः विकल्प (c) सही है।**
- इन मानकों को वर्ष 1977 में एक निकाय के रूप में गठित लेखा मानक बोर्ड (Accounting Standards Board-ASB) द्वारा तैयार किया गया था।
 - ASB, ICAI (Institute of Chartered Accountants of India) के अंतर्गत गठित एक समिति है जिसमें सरकारी विभागों,

शिक्षाविदों, अन्य पेशेवर निकायों जैसे ASSOCHAM, CII, FICCI, आदि के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

- Ind AS को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS) के अनुसार तैयार किया गया है।

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. उप-राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
2. अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उप-राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
3. उप-राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जाँच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2
- c. केवल 2 और 3
- d. केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- राष्ट्रपति की तरह उप-राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है (अनुच्छेद 66)।
 - वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्यों) के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
 - **11वें संविधान संशोधन (1961)** द्वारा उप-राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया था जिसके तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान की जगह निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।
- उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है (अनुच्छेद 67)। हालाँकि वह अपनी



पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे हटाने के लिये औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। संविधान में उसे हटाने के हेतु किसी आधार का उल्लेख नहीं है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- जब उप-राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
- उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जाँच व निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। **अतः कथन 3 सही है।**

42. वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यह केंद्रीय और राज्य GST कानूनों के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा।
 2. यह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

- GSTAT की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थापित की गई है। GSTAT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं इसमें एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।
- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जी.एस.टी. कानूनों में दूसरी अपील का मंच है और केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद

समाधान का प्रथम साझा मंच है। **अतः कथन 2 सही है।**

- केंद्र और राज्य, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रथम अपीलों में दिये गए आदेशों के विरुद्ध अपील, GST अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल की जाती है जो कि केंद्र तथा राज्य जी.एस.टी. अधिनियमों के अंतर्गत एक ही होता है। **अतः कथन 1 सही है।**
- साझा मंच होने के कारण GSTAT सुनिश्चित करेगा कि जी.एस.टी. के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे विवादों के समाधान में एकरूपता होगी और इस प्रकार समूचे देश में जी.एस.टी. को समान रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

43. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है, जिन पर संसद विधि बना सकती है।
2. जब संसद के सदनों में से कोई एक सदन ही सत्र में हो तब भी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
3. संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 3
- b. केवल 1 और 3
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- संविधान के **अनुच्छेद 123** के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियाँ, संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं परंतु ये प्रकृति में अल्पकालीन होते हैं।
- सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति, केवल समयावधि को छोड़कर, संसद की कानून बनाने की



शक्तियों के समविस्तीर्ण ही है। इसके दो निहितार्थ हैं:

- अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता जिन पर संसद कानून बना सकती है। अतः **कथन 1 सही है।**
 - अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएँ होती हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण नहीं कर सकता अथवा उसको छीन नहीं सकता।
 - राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो।
 - अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों द्वारा पारित किया जाना होता है न कि केवल एक सदन द्वारा। अतः **कथन 2 सही है।**
 - एक विधेयक की भाँति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है अर्थात् इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। यह किसी कर विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है।
 - हालाँकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतः **कथन 3 सही है।**
44. निम्नलिखित में से किसे/किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है?
1. वित्त आयोग के सदस्य
 2. केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री
 3. उप-राष्ट्रपति
 4. महान्यायवादी
 5. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
- नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1, 2, 4 और 5
- b. केवल 1, 4 और 5
- c. केवल 1, 2, 3 और 4
- d. 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, **महान्यायवादी**, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, **संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों**, राज्य के राज्यपालों, **वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों** की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
- **केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद ग्रहण करते हैं।
- राष्ट्रपति तरह उप-राष्ट्रपति, जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः **विकल्प (a) सही है।**

अतिरिक्त जानकारी

- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है।
 - वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति जानने के लिये आयोग का गठन कर सकता है।
 - वह केंद्र-राज्य तथा अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है।
 - वह प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित करता है।
45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु संसद में पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकता है।



2. बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के, कर आरोपित करने वाला कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- संविधान के भाग XX के अनुच्छेद-368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है।
- संविधान के संशोधन का आरंभ इस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद के दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, न कि राज्य विधान मंडल में। **इसके लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।**

- 24वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति के लिये संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है। वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लौटा सकता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- भारतीय संविधान में बजट के क्रियान्वयन के संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं, जैसे- बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
- कर आरोपित वाला कोई धन राष्ट्रपति के संस्तुति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इस प्रकार का विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। **अतः कथन 2 सही है।**

46. राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने से पूर्व भारतीय संसद को आवश्यकता होती है:

- राज्यसभा से अनुमोदन की
- राष्ट्रपति से स्वीकृति की
- आधी राज्य विधान सभाओं द्वारा प्रस्ताव के पारित होने की

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 2
- केवल 1 और 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- संविधान का अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने के लिये संसद की शक्ति से संबंधित है।
- यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई या अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित कर दिया है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक या उपयुक्त है कि संकल्प में निर्दिष्ट राज्य सूची के संदर्भ में संसद को किसी भी मामले के संबंध में विधि बनानी चाहिये तो संसद द्वारा राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाया जा सकता है।
- संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे यह संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। इसके लिये उसे **राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य सूची के संदर्भ में विधि बनाने की राज्यसभा की शक्ति अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है। अतः कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है।**
- विशेष परिस्थितियों में जैसे - राष्ट्रपति का चुनाव जैसे उपबन्धों में संविधान संशोधन हेतु आधी विधान सभाओं का समर्थन आवश्यक है। **राज्यसूची के किसी विषय पर विधि बनाने के लिये इस तरह के संकल्प की आवश्यकता नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है।**

47. निम्नलिखित में से किस/किन परिस्थिति/परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है?

- केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन समय।



2. जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो, तो लोकसभा को विघटित करने में।
3. मंत्रिपरिषद को विघटित करने में, यदि वह लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर पाए।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राष्ट्रपति को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है।
 - दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी है। वहीं, 44वें संशोधन में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिये कह सकता है। राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिये मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिये वह बाध्य है।
- यद्यपि, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है:
 - लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट

उत्तराधिकारी न हो तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।

- वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। **अतः कथन 3 सही है।**
- वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो। **अतः कथन 2 सही है।**

- यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है कि वह उसके द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित करे। यह राष्ट्रपति के परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. मंत्रिमंडलीय समितियाँ संविधानेत्तर निकाय हैं और इनका नेतृत्व केवल प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है।
2. मंत्रिमंडलीय समितियों में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल किये जाते हैं।
3. राजनीतिक मामलों संबंधी समिति केंद्रीय सचिवालय में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2 और 3
- c. केवल 3
- d. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- मंत्रिमंडलीय समितियाँ गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर निकाय हैं। दूसरे शब्दों में, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तथापि कार्य-नियमों (Rules of Business) में इनकी स्थापना की बात कही गई है। आम तौर पर, इन समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। **कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इन समितियों के**



अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर-कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- राजनीतिक मामलों संबंधी समिति घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतिरिक्त जानकारी

- जून 2019 में, सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय समितियों के साथ दो नई समितियों का गठन किया गया था। वर्तमान में निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय समितियों हैं-
 1. नियुक्तियों पर मंत्रिमंडलीय समिति
 2. आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति
 3. आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
 4. संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
 5. राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति
 6. सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति
 7. निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति
 8. रोजगार तथा कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति
- 49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।
 2. लोकसभा के विघटन के पश्चात् भी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त नहीं होता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2

- c. 1 और 2 दोनों
- d. न ही 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **अनुच्छेद 74:** इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सलाह देती है। राष्ट्रपति उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
 - वर्ष 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “लोकसभा के विघटन होने के पश्चात् भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी।” अनुच्छेद-74 अनिवार्य है और इस प्रकार, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता है।
 - बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद-74 का उल्लंघन माना जाएगा। **अतः कथन 1 और 2 सही हैं।**
 - मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
 - जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी।
50. भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों से राष्ट्रपति को संसूचित करे।
 2. इसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है।
 3. संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते निर्धारित किये गए हैं, लेकिन कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 2
- b. केवल 1 और 2



- c. केवल 2 और 3
d. केवल 1 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 78** प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचनाएँ प्रदान करने संबंधी कर्तव्य को परिभाषित करता है। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह-
 - संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे,
 - संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी, जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और
 - किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा, किये जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिये रखे। **अतः कथन 1 सही है।**
- संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद-75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं, न कि संविधान द्वारा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

51. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. देश में वहनीय/विश्वसनीय तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना इसका उद्देश्य है।

2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- PMSSY का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य रूप से देश में सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्तर स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है और विशेष रूप से कमज़ोर या पिछड़े राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं में वृद्धि करना है। **अतः कथन 1 सही है।**

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- एम्स (AIIMS) की स्थापना के अलावा PMSSY देश के विभिन्न राज्यों के कई वर्तमान सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के उन्नयन की भी परिकल्पना करता है।

52. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण में 50:50 की साझेदारी वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

2. इसका उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है।

3. यह योजना भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?



- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय वयोश्री योजना **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (Senior Citizens' Welfare Fund) से वित्तपोषित **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। वर्ष 2016 में इस कोष को अधिसूचित किया गया था। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है जो अल्प दृष्टि, श्रवण दोष, दंत-क्षय और चलन विकलांगता जैसी आयु संबंधी निःशक्तता के शिकार हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- यह योजना **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। **अतः कथन 3 सही है।**

53. 'किशोरियों के लिये योजना (SAG)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है।
- योजना का लक्ष्य-समूह 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की सभी किशोरियाँ हैं।
- इसे एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- किशोरियों के लिये योजना** (Scheme for Adolescent Girls- SAG) एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिसका नोडल मंत्रालय **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- योजना का लक्ष्य-समूह 11-14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियाँ हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा या व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण की ओर उन्मुख होने के लिये प्रेरित करना है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- इसे एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। **अतः कथन 3 सही है।**

54. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पी.एम.-एस.वाई.एम.) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ हेतु पात्र हैं।
- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक है।

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक** जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए प्रतिमाह या उससे कम है और 18-40 वर्ष आयु वर्ग के हैं, इस योजना के पात्र हैं। **अतः कथन 1 सही है।**

- ऐसा कोई पात्र व्यक्ति पहले से नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम



(ESIC) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO योजना में शामिल नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, वह आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

- यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका प्रबंधन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा कार्यान्वयन जीवन बीमा निगम (LIC) और CSC-ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- PM-SYM 50:50 के अनुपात के आधार पर एक **स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना** है, जिसमें निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा उसके बराबर का अंशदान किया जाएगा। **अतः कथन 3 सही है।**

55. 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जहाँ सरकार द्वारा 45% तक की सब्सिडी प्रदान कराई जाती है।
2. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम** (Prime Minister's Employment Generation Programme- PMEGP) एक **क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना** है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोज़गार को बढ़ावा देती है और इसके लिये MSME मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा अधिकतम 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) राष्ट्रीय स्तर पर PMEGP के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर इसे राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIBs), ज़िला उद्योग केंद्र (DICs) और बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एक सांविधिक निकाय है।
2. संविधान का अनुच्छेद-48 समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिये निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है।
3. केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (CVCF) योजना बलात्कार, एसिड अटैक और मानव तस्करी आदि की पीड़िताओं को सहायता प्रदान करती है।
4. निर्भया कोष का उपयोग केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष योजना में किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 1 और 3
- c. केवल 1, 3 और 4
- d. केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है, जो समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक तंत्र की स्थापना के लिये वर्ष 1995 में प्रभाव में आया। यह एक सांविधिक निकाय है। **अतः कथन 1 सही है।**
- समाज के गरीब और कमज़ोर तबकों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का उपबंध अनुच्छेद 39A में किया गया है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- संविधान का अनुच्छेद-48 राज्य को निर्देश देता है कि वह गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं



एवं वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाए।

- सरकार ने बलात्कार, एसिड अटैक, मानव तस्करी और सीमा-पार गोलीबारी की शिकार पीड़िताओं की सहायता के लिये वर्ष 2015 में केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (Central Victim Compensation Fund-CVCF) योजना शुरू की थी। **अतः कथन 3 सही है।**

- CVCF में निर्भया कोष का प्रयोग किया जा रहा है। यह महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिये एक गैर-व्यपगत समग्र निधि है। **अतः कथन 4 सही है।**

57. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
2. यह वार्षिक रूप से 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना भंडारण कार्य के लिये गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी ताकि खोजकर्त्ताओं को अपराध एवं अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके।

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस कमीशन (1977-1981) की टंडन समिति तथा गृह मंत्रालय की टॉस्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो वर्तमान में इन प्रभागों के माध्यम से कार्य कर रहा है:

- अपराध रिकार्ड शाखा
- केंद्रीय अंगुलि छाप ब्यूरो
- सांख्यिकीय शाखा
- प्रणाली विकास शाखा
- राज्य कार्यान्वयन शाखा
- प्रणाली अनुरक्षण शाखा
- प्रशिक्षण शाखा
- आँकड़ा केंद्र और तकनीकी शाखा।

- वर्ष 2009 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) परियोजना की देख-रेख, समन्वय तथा अमल में लाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

- NCRB 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के माध्यम से देश भर में अपराध के व्यापक वार्षिक आँकड़े प्रस्तुत करता है। **अतः कथन 2 सही है।**

58. उजाला (UJALA) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
2. यह एक स्टीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम है जो पारंपरिक सड़क प्रकाश बल्बों को LEDs से प्रतिस्थापित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) अर्थात् उन्नत ज्योति द्वारा सभी के लिये रियायती एलईडी (उजाला) कार्यक्रम का क्रियान्वयन विद्युत मंत्रालय की संयुक्त उपक्रम सार्वजनिक कंपनी एनर्जी एफिशंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा किया जा रहा है। LED आधारित घरेलू सक्षमता लाइटिंग कार्यक्रम (DELP) को 'उजाला' नाम दिया गया है। **अतः कथन 1 सही है।**



- उजाला योजना पारंपरिक तापदीप्त बल्बों को LED बल्बों से प्रतिस्थापित करने और घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा-कुशल प्रणालियों को अपनाने में एलईडी की उच्च लागत को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है।
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Programme-SLNP) एक सड़क प्रकाश प्रतिस्थापन कार्यक्रम है जो पारंपरिक सड़क प्रकाश बल्बों को LEDs से प्रतिस्थापित करता है।

अतः कथन 2 सही नहीं है।

59. 'जैविक खाद्य बाज़ार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत विश्व का सबसे बड़ा जैविक बाज़ार है।
2. सिक्किम विश्व का पहला जैविक राज्य है।
3. भारतीय जैविक खाद्य क्षेत्र मुख्य रूप से घरेलू माँग से प्रेरित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. केवल 1 और 3
- d. केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जैविक बाज़ार (organic market) है। इसके बाद जर्मनी, फ्राँस, चीन, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- सर्वाधिक जैविक कृषि भूमि के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है और भारत में जैविक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है।
 - सिक्किम विश्व का पहला जैविक राज्य (organic state) है। **अतः कथन 2 सही है।**
- भारतीय जैविक खाद्य क्षेत्र (Organic food sector) मुख्य रूप से निर्यात द्वारा संचालित है जो बाज़ार मूल्य का लगभग 80% है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
- भारतीय ऑर्गेनिक सेक्टर-विज्ञान 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ऑर्गेनिक

कारोबार के वर्ष 2025 तक 75,000 करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है।

60. नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHFDC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है।
2. यह दिव्यांगजनों के लिये कई कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन करता है।

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- NHFDC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तत्वावधान में एक सर्वोच्च निगम है। **अतः कथन 1 सही है।**
- यह कंपनी अधिनियम के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- यह दिव्यांगजनों को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा उन्हें अपने उद्यमों को विकसित करने और उनको सशक्त बनाने के लिये विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ देता है। **अतः कथन 2 सही है।**

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. व्यापार संतुलन शब्दावली में भुगतान संतुलन की तुलना में लेन-देन की अधिक विस्तृत शृंखला शामिल है।
2. भुगतान संतुलन का चालू खाता केवल वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात को शामिल करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)



व्याख्या:

- किसी देश के विदेशी लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिये भुगतान संतुलन (BoP) खातों को व्यवस्थित किया जाता है और ये राष्ट्रीय आय खातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। किसी देश का BoP किसी निश्चित समय के दौरान सूचीबद्ध देश के निवासियों और विदेशी निवासियों के बीच सभी प्रकार के लेन-देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है।

व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन

- व्यापार संतुलन केवल ऐसे लेन-देन से संबंधित है जो वस्तुओं के निर्यात और आयात से जुड़े होते हैं। इसमें सेवाओं के आदान-प्रदान पर विचार नहीं किया जाता है।
- भुगतान संतुलन वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान पर केंद्रित होता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

चालू खाता

- इसमें वस्तुओं, सेवाओं के आयात एवं निर्यात तथा अंतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्राप्तियाँ हैं जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं अर्थात् ऐसे भुगतान जो किसी देश के निवासी बदले में कोई भी वस्तु या सेवा दिये बिना प्राप्त करते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

62. भारत सरकार द्वारा ने 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर राष्ट्रीय मिशन' लॉन्च किया है।

GeM का उद्देश्य क्या है?

- a. केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिये सामान्य प्रयोग की वस्तु एवं सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन हेतु एक बिंदु-स्थित सुविधा प्रदान करना।
- b. छोटे ग्रामीण कारीगरों के लिये प्रत्यक्ष रूप से हस्तशिल्प वस्तुओं को बेचने के लिये एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना।
- c. कृषि उपज बिक्री के लिये किसानों तथा व्यापारियों को जोड़ना।
- d. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा GeM को अपनाने और प्रयोग में तेज़ी लाने के लिये गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है।

- इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में समावेशन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना तथा नकद रहित, संपर्क रहित एवं कागज़ रहित लेन-देन प्राप्त करना है। इससे समग्र रूप से दक्षता में वृद्धि होगी और खरीद पर किये गए सरकारी व्यय पर लागत बचत होगी।

- GeM सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबद्ध निकायों के लिये वस्तु एवं सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिये स्थापित एक ऑनलाइन बाज़ार है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

63. बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस नीति का उद्देश्य घरेलू बौद्धिक संपदा अधिकार को दायर करने को सुविधाजनक बनाना है।
2. इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए IPR को एक विपणन योग्य वित्तीय संपत्ति के रूप में आगे बढ़ाना तथा नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
3. यह नीति WTO के TRIPS समझौते के अनुरूप है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:



- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन नियम, 2007 में दो संशोधन किये हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018 में पेटेंट अधिनियम, 1970 के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है।

- यह अधिकार-धारक को बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित किसी भी संशोधन, रद्दीकरण, निलंबन या प्रतिक्रिया के बारे में सीमा-शुल्क आयुक्त को सूचित करने के लिये बाध्य करता है, साथ ही सीमा-शुल्क प्राधिकरणों के लिये भी तदनुसार प्रदत्त रक्षा को संशोधित, निलंबित या निरस्त करना अनिवार्य करता है।

- भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के IPR के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते अर्थात् ट्रिप्स समझौते के अनुरूप है और इसका लक्ष्य उद्यमिता को बनाए रखना एवं 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना है। **अतः कथन 3 सही है।**

- बौद्धिक संपदा अधिकार एक व्यक्ति या कंपनी को प्राप्त ऐसा विशेष अधिकार है, जिसके द्वारा वह एक विशिष्ट अवधि के लिये प्रतिस्पर्द्धा की चिंता के बिना अपनी योजनाओं, विचारों या अन्य अमूर्त संपत्तियों का उपयोग करता है।

- इन अधिकारों में कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। यह एक मुकदमे के माध्यम से किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।

- इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए IPR को एक विपणन योग्य वित्तीय संपत्ति के रूप में आगे बढ़ाना, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। **अतः कथन 2 सही है।**

- इस नीति का उद्देश्य उत्पादन से लेकर वाणिज्यीकरण तक समग्र मूल्य शृंखला के लिये घरेलू बौद्धिक संपदा अधिकार को

फाइल करने को सुविधाजनक बनाना है। इसका लक्ष्य कर लाभों के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।

अतः कथन 1 सही है।

64. उत्पादन गतिविधि में 'मूल्यहास' पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण पूंजी की अप्रत्याशित या अचानक हुई क्षति को शामिल नहीं करता है।
2. यह एक प्रवाह चर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- मूल्यहास को पूंजी के नियमित क्षय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक पूंजीगत वस्तु के क्षय के लिये वार्षिक भत्ता है।
- अप्रत्याशित या अचानक विनाश या पूंजी के दुरुपयोग, जो दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या ऐसी अन्य बाह्य परिस्थितियों के कारण होता है, को मूल्यहास नहीं कहा जाता है। **अतः कथन 1 सही है।**
- 'प्रवाह चर' एक ऐसी मात्रा है जिसे समय की अवधि के संदर्भ में मापा जाता है, जबकि स्टॉक चर एक ऐसी मात्रा है जिसे समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है।
- मूल्यहास को समय की अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या को लागत से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसलिये यह एक प्रकार का प्रवाह चर है। **अतः कथन 2 सही है।**

65. निम्नलिखित में से कौन-से सरकार के बजट के उद्देश्य हैं?

1. सकल घरेलू उत्पाद विकास की उच्च दर को बनाए रखना
2. आय और धन का पुनर्वितरण
3. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना



नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

सरकारी बजट वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों (Receipts) और सरकारी व्ययों को पूरा करने के साधनों का एक विवरण होता है।

सरकारी बजट के उद्देश्य

- **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की उच्च दर:** अपने राजस्व और व्यय नीति के माध्यम से सरकार GDP वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह सड़कों, बांधों, पुलों सहित बुनियादी ढाँचे पर निवेश व्यय करती है। उच्च निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। **अतः कथन 1 सही है।**

- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** आधारभूत विकास के लिये धन आवंटित करते समय देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- **आय और धन का पुनर्वितरण:** आर्थिक विभाजन की समस्या का मुकाबला सरकार की राजस्व और व्यय नीति से होता है। इस संदर्भ में कराधान और सब्सिडी प्रमुख नीतिगत साधन हैं। उच्च आय पर कराधान की उच्च दर और कम आय पर कराधान की न्यून दर से अमीरों और गरीबों की प्रयोज्य आय (वह आय जो एक व्यक्ति के पास, सरकार द्वारा उसकी आय तथा संपत्ति पर लगाए जाने वाले सभी करों को घटाने के बाद बचती है) (Disposable Income) के बीच खाई को कम करती है। **अतः कथन 2 सही है।**

- **रोज़गार के अवसर:** सार्वजनिक उद्यमों में निवेश और प्रशासनिक सेवाओं के प्रावधान रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं। उदाहरण-मनरेगा। **अतः कथन 3 सही है।**

66. वोस्ट्रो खातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक ऐसा खाता है जो एक अभिकर्ता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है।
2. भारत में डीलर बैंकों को प्रत्येक बार वोस्ट्रो खाता खोलने से पहले RBI की अनुमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

वोस्ट्रो खाता

- वोस्ट्रो एक ऐसा खाता है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिये रखता है। वोस्ट्रो खाता एक **संपर्ककर्ता बैंक (Correspondent Bank)** द्वारा दूसरे बैंक के निमित्त रखा जाने वाला बैंक खाता है। ये खाते संपर्ककर्ता बैंकिंग का एक अनिवार्य पहलू हैं, जिसमें धन रखने वाला बैंक विदेशी समकक्ष के खाते के संरक्षक के रूप में कार्य करता है या उसका प्रबंधन करता है। **अतः कथन 1 सही है।**

- उदाहरण के लिये यदि स्पेन की कोई जीवन बीमा कंपनी स्पेनिश जीवन बीमाकर्ता की ओर से धन का प्रबंधन करने के लिये किसी अमेरिकी बैंक से संपर्क करती है, तो धारक बैंक द्वारा उस खाते को बीमा कंपनी का वोस्ट्रो खाता माना जाता है।

भारत में

- रुपया आहरण व्यवस्था (Rupee Drawing Arrangements-RDAs) के संबंध में भारतीय बैंकों द्वारा गैर-निवासी विनिमय संस्थाओं के वोस्ट्रो खाते खोलने और उनके रख-रखाव के लिये पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता था। इस व्यवस्था को अधिक परिचालन अवसर देने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह आवश्यकता समाप्त कर दी।
- अनुमोदित डीलर बैंक अब खाड़ी देशों, हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर और मलेशिया एवं FATF का अनुपालन करने वाले अन्य सभी



देशों (जो केवल 'शीघ्र विपणन प्रक्रिया' के तहत FATF का अनुपालन करते हों) के गैर-निवासी विनिमय संस्थाओं के साथ ऐसी व्यवस्था में प्रथम बार प्रवेश करते समय ही भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने को बाध्य होंगे।

- इसके बाद वे RDA's में प्रवेश कर सकते हैं और फिर इसकी त्वरित सूचना RBI को दे सकते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

67. बैंकिंग लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।
2. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 'बैंकिंग लोकपाल योजना' बैंकों द्वारा प्रदत्त कतिपय सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिये बैंक ग्राहकों को उपलब्ध एक त्वरित और अल्प-व्यय मंच है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 A के तहत पेश की गई। यह वर्ष 1995 से प्रभाव में है।
- वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 (1 जुलाई, 2017 तक संशोधित) कार्यान्वयन में है।
- 'बैंकिंग लोकपाल' नामक एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। वह कुछ विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं में कमी के विरुद्ध आई ग्राहक की

शिकायतों को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होता है।

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत आते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**

68. पंद्रहवें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित होने वाले करों के निर्धारण के लिये इसके द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का प्रयोग किया गया।
2. विभाज्य करों में राज्यों के अंश के निर्णय के लिये पहली बार वन क्षेत्र के मानक को शामिल किया गया है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- 15वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से राज्यों को हस्तांतरित होने वाले करों के लिये जनगणना 1971 को आधार मानदंड मानने की बजाय जनगणना 2011 के आँकड़ों का प्रयोग करने की सिफारिश की है। **अतः कथन 1 सही है।**
- कई राज्यों को आशंका है कि इससे विभाज्य करों के उनके हिस्से में कमी हो सकती है। इसके अलावा, वे इसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये एक दंड के रूप में देखते हैं।
- आयोग को प्रस्तुत एक ज्ञापन में राज्य सरकारों ने कहा कि आधार आबादी के आँकड़े में परिवर्तन उन राज्यों के करों के क्षैतिज हिस्से को दंडित करेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार आबादी की प्रतिस्थापन दर तक पहुँचने के लिये सफल पहले की थी।
- आयोग के लिये, राज्यों के हिस्से के निर्धारण के लिये जनसंख्या एक सतत् मानक रहा है।



12वें और 13वें आयोग के अंतर्गत, जनसंख्या को 25% भारांश दिया गया था, जबकि 14वें आयोग ने इसे 17.5% का भारांश दिया।

- अन्य मानकों में आय दूरी, वन आच्छादन, भौगोलिक क्षेत्र, राजकोषीय अनुशासन और कर प्रयास शामिल हैं।
- **15वें आयोग के विचारार्थ विषय से वन आच्छादन के मानक को हटा दिया गया, जिसे पहली बार 14वें आयोग में ही शामिल किया गया था।** इसकी बजाय केंद्र सरकार ने नवीनतम आयोग से जलवायु परिवर्तन, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे के विकास और विस्तार तथा प्रभावी रेलवे की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करने की अपेक्षा की है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

69. सीमांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों को एक रात के लिये निधि उपलब्ध कराता है।
2. यह दर सदैव रेपो दर से अधिक होती है।
3. इसे संपार्श्विक जमानत के रूप में निर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध जारी किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- a. केवल 1 और 3
- b. केवल 1 और 2
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- 'सीमांत स्थायी सुविधा' (Marginal Standing Facility) बैंकों में अचानक तरलता/नकदी में भारी कमी आ जाने की आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को ऋण लेने के लिये दी गई सुविधा है। इसके तहत अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों (RBI अधिनियम, 1934 की अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध) को अल्पकालिक अवधि के लिये तत्काल ऋण दिया जाता है। **अतः कथन 1 सही है।**

- रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) पर संपार्श्विक के रूप में 'सीमांत स्थायी सुविधा' (MSF) के माध्यम से बाज़ार प्रतिभागियों को तरलता/चलनिधि प्रदान करता है। हालाँकि इस सुविधा के तहत भारतीय प्रतिभूतियों पर RBI द्वारा दिया गया ऋण, रेपो दर से अधिक दर पर दिया जाता है।

- 'संपार्श्विक' (collateral), संपत्ति या अन्य परिसंपत्ति है, जिसे एक ऋणधारक ऋण पर सुरक्षा के रूप में ऋणदाता को प्रदान करता है।
- MSF दर सामान्यतः 100 आधार अंक या रेपो दर से एक प्रतिशत अंक अधिक होती है। **अतः कथन 2 और 3 सही हैं।**

- रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के साथ MSF भी बाज़ार में तरलता की स्थिरता बनाए रखने के लिये RBI की तरलता समायोजन सुविधा का हिस्सा बन गया है।
- चूंकि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निधि की सख्त ज़रूरत होती है इसलिये RBI इसे एक अवसर के रूप में लेता है और रेपो दर की तुलना में उच्च दर पर ऋण प्रदान करता है।

70. अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances-WMA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गए अल्पकालिक ब्याज-मुक्त ऋण हैं।
2. इन ऋणों को संपार्श्विक जमानत के साथ या बिना भी जारी किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों



d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- RBI केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। यह समझौते के माध्यम से सरकारों को उनकी प्राप्तियों (Receipts) और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों को संतुलित करने में मदद करने के लिये, उनके लिये वित्तीय अनुकूलन प्रदान करता है।
- 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) RBI द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के बीच किसी भी अंतर को संतुलित करने के लिये दी गई अल्पकालिक अग्रिम धनराशि (ब्याज सहित) है। WMA सामान्यतः ब्याज शुल्क के लिये रेपो दर से जुड़ा होता है। ये ब्याज मुक्त ऋण नहीं होते हैं। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किये जाने वाले WMA दो प्रकार के होते हैं: विशेष अर्थोपाय अग्रिम और सामान्य अर्थोपाय अग्रिम।
- जब राज्य सरकारें संपार्श्विक प्रतिभूतियों Collateral Securities पर ऋण लेती हैं तो इसे विशेष अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है, अन्यथा इसे सामान्य अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है।
- RBI 90 दिनों की अवधि के लिये सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार अर्थोपाय अग्रिम संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बिना भी जारी किया जा सकता है। **अतः कथन 2 सही है।**

71. परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से राष्ट्रीय आय से घटाया जाना चाहिये?

1. सरकार द्वारा परिवारों को किया गया अंतरण भुगतान
2. परिवारों द्वारा किया गया निवल ब्याज भुगतान
3. अवितरित लाभ

4. कॉर्पोरेट कर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. 1, 2, 3 और 4
- b. केवल 2, 3 और 4
- c. केवल 3 और 4
- d. केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय आय, जो संगठनों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती है, में लाभ का एक हिस्सा शामिल होता है जो उत्पादन कारकों के बीच वितरित नहीं होता है। इसे **अवितरित लाभ** कहा जाता है।
- अन्य शब्दों में किसी कंपनी की इक्विटी का अविभाजित लाभ एक हिस्सा है और शेयरधारकों के स्वामित्व के अधीन होता है। इन्हें प्रतिधारित आय के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। व्यक्तिगत आय ज्ञात करने के लिये अवितरित लाभ को राष्ट्रीय आय से घटाया जाना चाहिये क्योंकि यह लाभ परिवारों को देय नहीं होता है।
- कॉर्पोरेट टैक्स, जो फर्मों द्वारा की गई आय पर आरोपित किया जाता है, को भी राष्ट्रीय आय (NI) से घटाया जाना चाहिये, क्योंकि यह परिवारों को देय नहीं होता है।
- परिवारों को निजी कंपनियों या सरकार से उनके द्वारा पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान प्राप्त होता है। साथ ही परिवारों द्वारा फर्मों और सरकार को भी ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है, यदि उन्होंने उनसे ऋण लिये हैं। इसलिये हमें व्यक्तिगत आय को प्राप्त करने के लिये फर्मों और सरकार को परिवारों द्वारा भुगतान किये गए निवल ब्याज को राष्ट्रीय आय से घटाना होगा।
- परिवारों को सरकार और फर्मों (उदाहरणस्वरूप पेंशन, छात्रवृत्ति, पुरस्कार) के रूप में भुगतान प्राप्त होता है, जिसे परिवारों की व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिये जोड़ा जाता है। **अतः विकल्प (b) सही है।**



72. निम्नलिखित में से कौन-से चीन के संबंध में भारत के निर्यातों के कमजोर रहने के संभावित कारण हैं?

1. बाजारों एवं उत्पादों के निम्न विशेषीकरण के साथ उच्च विविधीकरण
2. वैश्विक मूल्य शृंखला में भागीदारी का निम्न स्तर
3. उच्च आय वाले देशों में बाजार तक कम पहुँच

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 1 और 3
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में चीन के निर्यातों की तुलना में भारत के निर्यातों के कमजोर रहने के कारणों की जाँच और गणना की गई है:
- **बाजारों और उत्पादों के कम विशेषीकरण के साथ उच्च विविधीकरण:**
 - भारत बाजारों एवं उत्पादों के विशेषीकरण के मामले में चीन से बहुत पीछे है। हालाँकि भारत उत्पादों व बाजारों में विविधीकरण के संबंध में चीन के साथ पकड़ बना रहा है।
 - कम विशेषीकरण के साथ उच्च विविधीकरण का तात्पर्य है कि भारत कई उत्पादों और भागीदारों पर अपने निर्यात का विस्तारित कम करता है, जिससे चीन की तुलना में इसका प्रदर्शन कमजोर रहता है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) में भागीदारी का निम्न स्तर:** पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में GVC में भारत की भागीदारी कम रही है।
 - वास्तव में चीन से पूंजी गहन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से GVC में उसकी भागीदारी

से प्रेरित है। 1990 के दशक के बाद से चीन की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों ने घरेलू उद्योगों को GVC के साथ एकीकृत करने की रणनीति पर बहुत अधिक जोर दिया है।

- **उच्च आय वाले देशों में बाजार तक निम्न पहुँच:** भारत जैसे विकासशील देशों, विशेष रूप से GVC में भागीदारी के निम्न स्तर के साथ, धनी देशों में गुणवत्ता/ब्रांड के प्रति सजग बाजारों के लिये पूंजी गहन उत्पादों का निर्यात करना बेहद कठिन है।

- वर्ष 2018 में उच्च आय और विकसित देशों में चीन के निर्यातों का हिस्सा 49.7% था, जबकि भारत के लिये यह आँकड़ा 40.2% था।

- इस प्रकार भारत की तुलना में चीन का उल्लेखनीय निर्यात प्रदर्शन संबंधित कारकों के एक समूह द्वारा संचालित है जैसे कि GVC में भागीदारी का एक उच्च स्तर; श्रम-गहन उत्पादन गतिविधियों में विशेषज्ञता की एक उच्च स्थिति; बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्र; और पारंपरिक धनी देशों में निर्यात पहुँच का उच्च स्तर। **अतः विकल्प (d) सही है।**

73. भारत में कारोबार करने की सुगमता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह उद्यमशीलता, नवाचार एवं धन सृजन की कुंजी है।
2. संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और संविदा अनुपालन जैसे मानकों पर भारत निरंतर पिछड़ रहा है।
3. पिछले एक दशक में कारोबारी सुगमता रिपोर्ट में भारत के स्थान में निरंतर कमी आई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 1 और 3
- c. केवल 2 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:



- भारत ने वर्ष 2024-25 तक पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिये व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था को सुगम बनाना आवश्यक है। **व्यापार सुगमता (EODB)** आर्थिक अवसरों तक पहुँच बढ़ाने, लेन-देन की लागत कम करने एवं भ्रष्टाचार को कम करने में व्यवसायों को लाभ पहुँचाती है।

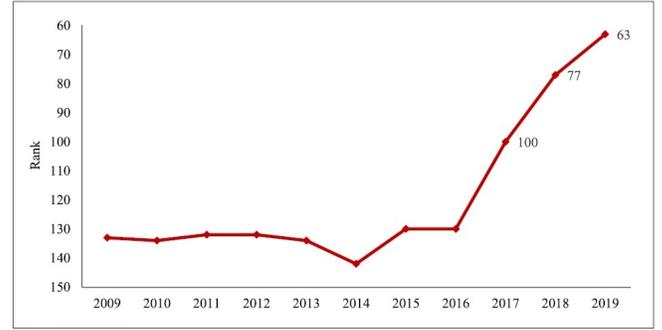
- इस प्रकार **EODB** उद्यमशीलता, नवाचार एवं धन सृजन की कुंजी है।
अतः कथन 1 सही है।

- व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिये शासन को अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिये मौजूदा नियमों के सरलीकरण और युक्तिकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के समावेशन करने पर ज़ोर दिया गया है।
- विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट- 2020 में भारत की 190 देशों में 63वाँ स्थान **EODB** में सुधार को दर्शाता है।

- यह रैंकिंग एक व्यवसाय के जीवन-चक्र आधारित 10 संकेतकों पर आधारित है। भारत ने 10 संकेतकों में से 7 में अपनी रैंक में सुधार किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट प्रथाओं के करीब पहुँच गया है।

- हालाँकि व्यवसाय शुरू करने की सुविधा, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और संविदा अनुपालन जैसे मापदंडों पर भारत का प्रदर्शन कमज़ोर बना हुआ है। **अतः कथन 2 सही है।**

- पिछले एक दशक में विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में निरंतर कमी नहीं आई है। वर्ष 2009-2013 के दौरान रैंकिंग लगभग स्थिर रही है परंतु वर्ष 2014 से इसके रैंकिंग में वृद्धि हुई है। (निम्नलिखित चित्र से इसे समझा जा सकता है) **अतः कथन 3 सही नहीं है।**



Source: World Bank.

चित्र: विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग

74. भारत के समग्र निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं के योगदान को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिये:

1. पेट्रोलियम उत्पाद
2. मोती, बहुमूल्य और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न
3. ड्रग सूत्रीकरण, जैविक उत्पाद
4. स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य धातु के आभूषण

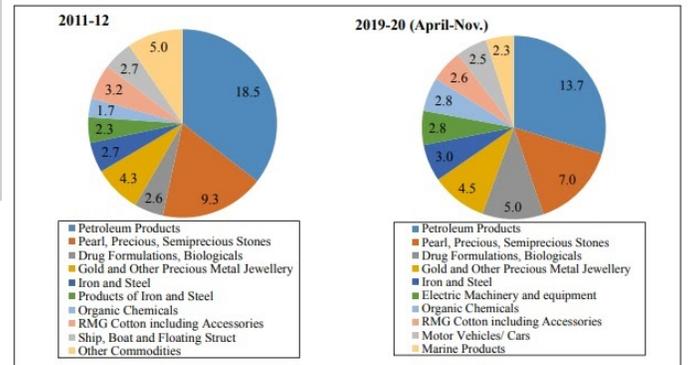
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. 1, 2, 3, 4
- b. 3, 1, 4, 2
- c. 4, 3, 2, 1
- d. 2, 1, 3, 4

उत्तर: (c)

व्याख्या:

Figure 9: Commodity-wise Composition of Exports (By Share in Per cent)



Source: Department of Commerce.

- वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यातों में 13.7% की हिस्सेदारी के साथ पेट्रोलियम उत्पाद सर्वाधिक निर्यात किये जाने वाले उत्पाद है।



- अन्य प्रमुख निर्यातों में मोती, बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य रत्न (7%), स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य धातु के आभूषण (4.5%) और ड्रग सूत्रीकरण एवं जैविक उत्पाद (5%) शामिल हैं। **अतः विकल्प (c) सही सुमेलित है।**
75. सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक-2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
- यह SDG-2030 को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करता है।
 - इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
 - सूचकांक में वर्गीकरण आकांक्षी, परफार्मर, फ्रंट रनर, अचीवर चार मानकों पर आधारित है।
 - उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य आकांक्षी श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- भारत में नीति आयोग 'सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक' जारी करता है जो देश और उसके राज्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण को लक्षित करता है।
- SDG भारत सूचकांक 2019 इस सूचकांक का दूसरा संस्करण है, जिसे वर्ष 2018 में पहली बार जारी किया गया था।
 - यह सूचकांक 2030 SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करता है।
- SDG भारत सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI), संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
- SDG सूचकांक-2019 हेतु समग्र स्कोर की गणना 16 SDG (SDG सूचकांक 2018 में

13 लक्ष्य) के समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिये 0-100 की रेंज में की जाती है।

- SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है:
 - आकांक्षी: 0-49
 - परफार्मर: 50-64
 - फ्रंट रनर: 65-99
 - अचीवर: 100

TOP 12, THE STATES

Kerala	70
Himachal	69
Andhra	67
Tamil Nadu	67
Telangana	67
Karnataka	66
Goa	65
Sikkim	65
Gujarat	64
Maharashtra	64
Uttarakhand	64
Punjab	62

BOTTOM 5, THE STATES

Bihar	50
Jharkhand	53
Arunachal	53
Meghalaya	54
UP, Assam	55

TOP 5, THE UTs

Chandigarh	70
Puducherry	66
Dadra & NH	63
Lakshadweep	63
Delhi, A&N Islands, Daman & Diu	61

- ध्यातव्य है कि SDG भारत सूचकांक-2019 में कोई भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आकांक्षी श्रेणी में नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं, लेकिन अभी भी परफार्मर श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।
76. अक्सर समाचारों में देखे गए 'वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज़म' संबंधित है:
- मानव अधिकार उल्लंघन से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से।
 - राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों के कार्यान्वयन से।
 - नाटो सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने से।
 - जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संबद्ध हानि एवं क्षति से।

उत्तर: (d)

व्याख्या:



- नवंबर 2013 में "व्यापक, एकीकृत तथा सुसंगत रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित हानि एवं क्षति को संबोधित करने के लिये दृष्टिकोण का कार्यान्वयन" के लिये UNFCCC जलवायु वार्ता (COP-19) में वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित किया गया था। **अतः विकल्प (d) सही है।**

77. भारत में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सूक्ष्म सिंचाई जल, बिजली और उर्वरकों जैसे आदानों के कुशल नियोजन में सहायक है।
2. सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष का प्रबंधन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- ड्रिप और स्पिंकलर सिंचाई युक्त सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक प्रमाणित तकनीक है जिसने किसानों के बीच अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। यह तकनीक जल, बिजली, उर्वरक, श्रम, फसल उत्पादकता में वृद्धि, आगतों के कुशल नियोजन, उचित मूल्य तथा उच्च गुणवत्ता वाले अग्रणी उत्पादों की प्राप्ति के साथ ही किसानों की आय वृद्धि में भी सहायक है। **अतः कथन 1 सही है।**
- इस तकनीक की सहायता से सिंचाई की पारंपरिक विधि की तुलना में जल की समान मात्रा से अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है।
- इसके अलावा सिंचाई सुगमता के फलस्वरूप पानी की कमी, जोत योग्य बंजर भूमि एवं अवनमित भूमि वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। चावल, गेहूँ, प्याज, आलू आदि

फसलों में इस तकनीक का उपयोग करने के अच्छे अवसर हैं।

- **नाबार्ड** के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए प्रारंभिक निधि एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund-MIF)** की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। यह राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिये संसाधन जुटाने और राज्य सरकारों की विशेष एवं अभिनव पहल के माध्यम से सिंचित क्षेत्र के विस्तार में भी सहायता कर रहा है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

78. 'संवृद्धि के सुचक्र' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. देश के सतत आर्थिक विकास के लिये यह सुचक्र महत्त्वपूर्ण है।
2. अचल निवेश दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी का एक मुख्य कारण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

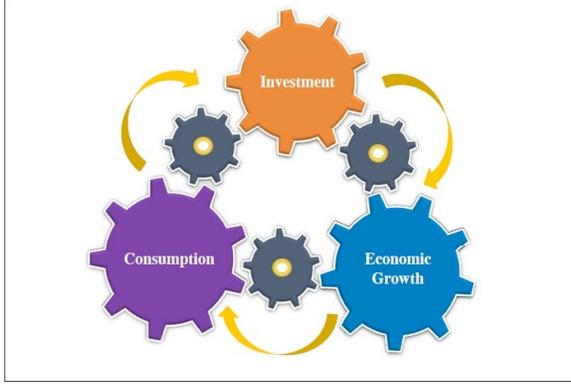
उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में संवृद्धि के सुचक्र (Virtuous Cycle of Growth) का वर्णन किया गया है जो:
 - अचल निवेश की दर में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को दर्शाता है जो उपभोग में अधिक वृद्धि का कारण बनता है।
 - उपभोग की अधिक वृद्धि निवेश में वृद्धि करती है, जिसके परिणामस्वरूप अचल निवेश में उच्च वृद्धि होती है जो उपभोग के उच्च वृद्धि को प्रेरित करते हुए GDP में वृद्धि को गति प्रदान करता है।
 - उच्च अचल निवेश-उच्च GDP वृद्धि-उच्च उपभोग वृद्धि का यह

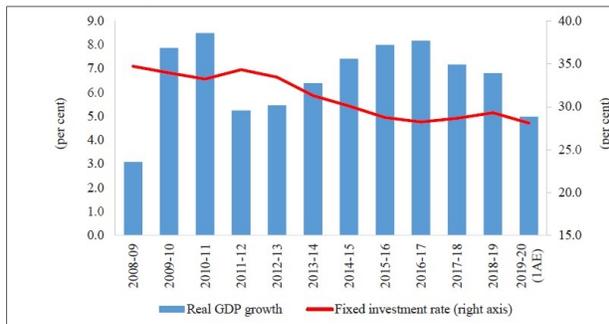


सुचक्र देश में सतत आर्थिक विकास को प्रेरित करता है।



चित्र: विकास का सुचक्र

- वर्ष 2011-12 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मंद चक्र से ग्रसित है। अचल निवेश दर में वर्ष 2011-12 के बाद से तेज़ी से गिरावट शुरू हुई है और वर्ष 2016-17 के बाद से यह स्थिर हो गया है।
 - GDP वृद्धि पर निवेश दर के पिछड़े प्रभाव को देखते हुए, वर्ष 2017-18 के बाद से वृद्धि में गिरावट 2011-12 के बाद से घटते निवेश के अनुरूप है।
 - इस प्रकार, अचल निवेश दर में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। इसे निम्नलिखित आलेख की सहायता से देखा जा सकता है। **अतः कथन 2 सही है।**



Data Source: National Statistical Office

चित्र: वास्तविक जीडीपी वृद्धि एवं निवेश -
वार्षिक गतिविधि

79. केंद्रीय कर राजस्व में निम्नलिखित कर स्रोतों के योगदान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिये:

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
2. वस्तु एवं सेवा कर (GST)
3. निगम कर
4. आय कर
5. सीमा शुल्क

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. 1, 2, 3, 5, 4
- b. 2, 3, 5, 4, 1
- c. 2, 3, 4, 5, 1
- d. 3, 2, 4, 1, 5

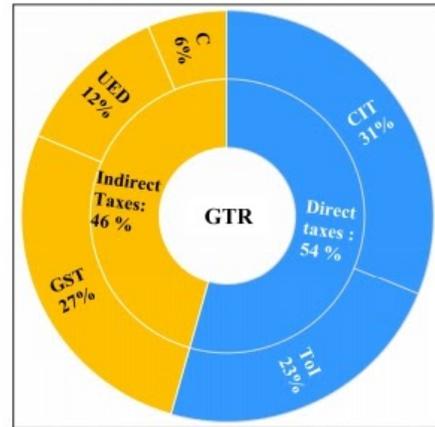
उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल कर राजस्व (GTR) की संरचना निम्नलिखित हैं:
 - निगम कर - 31%
 - GST - 27%
 - आय कर - 23%
 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क - 12%
 - सीमा शुल्क - 6%

अतः विकल्प (d) सही है।

Figure 3: Composition of taxes in Gross Tax Revenue in 2019-20 BE



Source: Union Budget Documents & CGA
GTR: Gross Tax Revenue, CIT: Corporation Tax, Tol: Taxes on Income other than Corporation Tax (includes STT), C: Customs, UED: Union Excise Duties, GST: Goods and Services Tax



80. बजट 2020-21 में उनके अनुमानित कुल व्यय के अवरोही क्रम में निम्नलिखित मंत्रालयों को व्यवस्थित कीजिये:

1. रक्षा मंत्रालय
2. गृह मंत्रालय
3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
4. रेलवे मंत्रालय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. 1, 2, 3, 4
- b. 2, 1, 3, 4
- c. 1, 3, 4, 2
- d. 2, 1, 4, 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- वर्ष 2020-21 में अनुमानित कुल व्यय का 53% भाग 13 उच्चतम आवंटन वाले मंत्रालयों से निर्मित है।
- अनुमानित कुल व्यय का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित है-
 - रक्षा मंत्रालय > गृह मंत्रालय > कृषि एवं किसान कल्याण > रेलवे मंत्रालय का है। अतः विकल्प (a) सही है।
- वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन किया गया है जो कि केंद्र सरकार के कुल बजटीय व्यय का 15% है।
- वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 में गृह मंत्रालय के आवंटन में 20.2% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के नव-गठित केंद्र शासित प्रदेशों को मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गए अनुदान के परिणामस्वरूप हुई है।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आवंटन में 30.1% की वृद्धि आई है। यह मुख्य रूप से PM-किसान योजना के आवंटन में वृद्धि के फलस्वरूप हुआ है।

81. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक संस्थागत तंत्र है।
2. यह व्यापार समुदाय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत एक संस्थागत तंत्र है जो व्यापार समुदाय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने वाली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने हेतु गठित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
 - व्यापारी समुदाय द्वारा उपभोक्ताओं से GST के नाम पर अधिक मूल्य की मांग करके अनुचित लाभ कमाने की गतिविधियों को नियंत्रित करना NAA का प्रमुख कार्य है। अतः कथन 2 सही है।
 - NAA यह सुनिश्चित करता है कि, GST परिषद द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं पर GST की दरों में कटौती तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट में आनुपातिक परिवर्तन का फायदा मौलिक उपभोक्ताओं और प्रापक को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से हो रहा है अथवा नहीं।
 - राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व इस प्रकार की मुनाफाखोरी का पता लगाकर उसकी जाँच करना और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करना है,



जिसमें लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है।

- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा चार तकनीकी सदस्य, प्रत्येक राज्य की स्थायी एवं अनुवीक्षण समितियाँ, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के अंतर्गत मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय के साथ मिलकर मुनाफाखोरी-रोधी मोर्चे पर साथ मिलकर कार्य करते हैं।

82. संविधान की पाँचवी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है।
2. राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं करने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- संविधान के भाग X के अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'जनजातीय क्षेत्र' नामित किया गया है, के लिये विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।
- संविधान की पाँचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है।
- पाँचवी अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।
- राज्य की कार्यकारी शक्ति, उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। परंतु ऐसे क्षेत्रों के लिये राज्यपाल पर विशेष ज़िम्मेदारी होती है।
- वह ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें।
- ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। **अतः कथन 1 सही है।**
- राज्य, जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं, में जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिये सलाह देती है।
- राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम विशेष अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न हो या कुछ परिवर्तन व अपवादों के साथ लागू हो। **अतः कथन 2 सही है।**

83. नागरिकता (अधिग्रहण और समाप्ति) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

- a. नागरिकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है।
- b. नागरिकता संविधान के 'बुनियादी ढाँचे' का हिस्सा नहीं है।
- c. नागरिकता संबंधी प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।
- d. नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 कुछ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने हेतु भारत में निवास की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करता है।



उत्तर: (d)

व्याख्या:

- संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा **साधारण बहुमत से संशोधित** किये जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएँ **अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर** हैं। इनमें शामिल हैं:

1. नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन।
2. राज्य विधानपरिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति।
3. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार
4. राजभाषा का प्रयोग।
5. **नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति**
6. संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिये निर्वाचन
7. निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
8. केंद्र शासित प्रदेश
9. पाँचवीं अनुसूची- अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
10. छठी अनुसूची- जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

- नागरिकता संविधान की **'मूल संरचना'** का **भाग नहीं** है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह परिभाषित या स्पष्ट करना बाकी है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। विभिन्न निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित तत्त्वों की मूल संरचना के भाग के रूप में **पहचान की जा सकती है।**

1. भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति
2. संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र
3. शक्तियों का विभाजन
4. संविधान का संघीय स्वरूप
5. कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
6. न्यायिक समीक्षा
7. विधि का शासन

8. समानता का सिद्धांत

9. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

10. **संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति।**

- नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के अनुसार अवैध प्रवासियों के कुछ विशिष्ट वर्गों के लिये नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास अवधि को **11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है, न कि 4 वर्ष। अतः विकल्प (d) सही नहीं है।**

84. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की समवर्ती शक्ति है।
2. क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है।
3. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2
- c. केवल 3
- d. केवल 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास **मृत्युदंड के निलंबन**, दंडावधि कम करने, दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में **समान शक्ति है** परंतु **मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है।**

- किसी राज्य कानून के अंतर्गत मृत्युदंड निर्धारित करने के बाद भी, क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**



- वर्ष 2006 में ईपुरु सुधाकर तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। **अतः कथन 3 सही है।**
- उनके निर्णय को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है-
 - इसे बुद्धिमत्तापूर्ण पारित न किया गया हो।
 - इसे बदनीयता से पारित किया गया हो।
 - यह अपरिपक्व या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर आधारित होकर पारित किया गया हो।
 - प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में न रखा गया हो।
 - यह स्वेच्छाचारिता से प्रभावित हो।

85. युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है।
2. यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपए के 'सहकारिता स्टार्ट-अप एवं नवाचार निधि' (CSIF) से संबद्ध की जाएगी।
3. योजना का लाभ लेने हेतु कम-से-कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ पात्र होंगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2 और 3
- c. केवल 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- युवाओं की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से, **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा 'युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना' तैयार की गई है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- NCDC ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक विशेष समर्पित कोष की स्थापना की है।
- यह योजना NCDC द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपए के 'सहकारिता स्टार्ट-अप एवं नवाचार निधि' (सी.एस.आई.एफ.) से लिंकड होगी। **अतः कथन 2 सही है।**
- यह पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं आकांक्षी जिलों की सहकारी संस्थाओं तथा महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग सदस्यों से संबंधित सहकारिता संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी।
- इन विशेष श्रेणियों के लिये वित्तपोषण परियोजना लागत का 80% तक एवं अन्य के लिये यह 70% होगा।
- जिन परियोजनाओं की लागत 3 करोड़ रुपए तक है उनके प्रोत्साहन के लिये योजना में ब्याज दर प्रचलित आवधिक ऋण (टर्म लोन) पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी, साथ ही मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष का अधिस्थगन (Moratorium) दिया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने हेतु कम-से-कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ पात्र होंगी। **अतः कथन 3 सही है।**

86. चुनावी बॉण्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बॉण्ड के माध्यम से चंदा लिया जा सकता है।
2. ये बॉण्ड किसी भी बैंक द्वारा के.वाई.सी. (अपने ग्राहक को जानिये) अनुरूप खाते को जारी किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2



उत्तर: (d)

व्याख्या:

एक चुनावी बॉण्ड को वचन-पत्र जैसे धारक साधन के रूप में तैयार किया गया है जो कि धारक की मांग पर देय होते हैं और ये ब्याजमुक्त होते हैं।

- बॉण्ड 1,000 रुपए, 10000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में तथा **भारतीय स्टेट बैंक** की निर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध हैं। उन्हें दानकर्ता द्वारा KYC अनुपालित खातों के माध्यम से खरीदा जा सकता है। दानकर्ता बॉण्ड को अपनी पसंद की पार्टी को चंदे के रूप में दे सकते हैं जिसे 15 दिनों के भीतर पार्टी के सत्यापित खाते से भुनाया/नकद किया जा सकता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 A के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त किया हो, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया जाएगा।

- केवल इस खाते के जरिये ही चुनावी बॉण्ड का लेन-देन हो सकता है।

अतः कथन 1 सही नहीं है।

- किसी भी वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के आरंभ में केवल 10 दिनों की अवधि के लिये बॉण्ड खरीद हेतु उपलब्ध होंगे अर्थात् जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में (जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट करें)। लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी।

87. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं?

1. गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार।
2. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश होने का अधिकार।

3. वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1 और 2
- b. केवल 2 और 3
- c. केवल 1 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

सामान्य स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इनमें गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार शामिल है।

- अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिये। CrPC धारा 56 और 76 में यह प्रावधान भी किया गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उक्त व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील/अधिवक्ता से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

- लेकिन, इनमें से कोई भी अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। **अतः विकल्प (d) सही है।**

- इसके अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में पाँच दिनों तक और असाधारण परिस्थितियों में 10 दिनों तक अनभिज्ञ रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए जाने के बाद भी सरकार उस व्यक्ति को उन सूचनाओं से अवरुद्ध रख सकती है जिनके खुलासे को वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध मानती है।

- गिरफ्तार व्यक्ति सलाहकार बोर्ड (जिसे सरकार द्वारा NSA संबंधी मामलों से



निपटने के लिये गठित किया जाता है) के समक्ष कार्यवाही से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी अधिवक्ता की सहायता का हकदार नहीं होता है।

88. वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. VVPAT प्रणाली मतदाता को तुरंत प्रतिपुष्टि करती है कि उसका मत उसके इच्छित प्रत्याशी को ही गया है।
2. VVPAT प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न वाली पर्ची मुद्रित करता है जिसे मतदाता प्राप्त कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

मतदाता पावती रसीद यानी वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि मतदाता द्वारा मतदान किया गया वोट उसकी पसंद के प्रत्याशी को ही गया है।

- VVPAT सत्यापन के लिये दूसरी पंक्ति का साधन है और विशेष रूप से ऐसे समय में यह काफी उपयोगी सिद्ध होता है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हो।
- VVPAT प्रणाली मतदाता को तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करती है जो यह दर्शाती है कि दिया गया मत वास्तव में चयनित प्रत्याशी के पक्ष में ही गया है। **अतः कथन 1 सही है।**
- मतदाता द्वारा EVM पर चयनित प्रत्याशी के लिये बटन दबाए जाने पर मशीन प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न वाली पर्ची मुद्रित करती है तथा यह स्वचालित रूप से एक बक्से में बंद हो जाती है। यह मशीन मतदाता को अपना वोट सत्यापित करने का अवसर

प्रदान करती है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- मशीन को काँच के बक्से में इस तरह रखा जाता है कि केवल मतदाता ही इसे देख सके। मतदाता को सात सेकेंड के लिये पर्ची दिखाई पड़ती है जिसके बाद VVPAT मशीन उसे पृथक् कर एक बीप के साथ बक्से में बंद कर देती है। **(इन मशीनों तक केवल मतदान अधिकारियों की पहुँच होती है, मतदाता की नहीं।)**

89. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 'विधि की उचित प्रक्रिया' सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है।
2. भारतीय न्यायपालिका केवल 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत का पालन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- अमेरिकी संविधान में उल्लिखित 'विधि की उचित प्रक्रिया' भारत के संविधान में वर्णित 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से दो मामलों में भिन्न है-

- 'विधि की उचित प्रक्रिया' सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिये व्यापक क्षेत्र और विधिक व्याख्या का अधिकार देती है और वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न केवल गैर-कानूनी होने के ठोस आधार पर बल्कि अतार्किक होने के प्रक्रियात्मक आधारों पर भी शून्य घोषित कर सकती है। **अतः कथन 1 सही है।**

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय इस बात की जाँच करता है कि कानून संबंधित



प्राधिकरण की शक्तियों के भीतर है अथवा नहीं। कानून की तार्किकता, उपयुक्तता या नीतिगत निहितार्थ के प्रश्न पर विचार करने की सर्वोच्च न्यायालय से आशा नहीं की जाती है।

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले (1978)** में **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा कि- अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'उचित, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष' होना चाहिये।

- यदि ऐसी कोई भी विधि 'स्वैच्छिक, काल्पनिक या दमनकारी' है तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया अनुच्छेद-21 की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम होंगी।

- इस प्रकार 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' ने भारत में वही स्थान प्राप्त कर लिया है, जो अमेरिका में 'विधि की उचित प्रक्रिया' का है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय के विरुद्ध भी उपलब्ध है।

90. 'सामाजिक सुरक्षा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के तहत सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख है।
3. हाल के दिनों में वैश्वीकरण ने सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को बढ़ाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. केवल 1 और 3
- d. 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वैश्वीकरण ने सरकार की नीतियों को प्रभावित कर उद्योगों के संकुचन, आउटसोर्सिंग और अनौपचारिक और

असंगठित क्षेत्र के आकार में वृद्धि कर सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को विशेष रूप से बढ़ा दिया है। अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिकूल श्रम बाज़ार निहितार्थों की प्रतिक्रिया के रूप में, सरकार द्वारा भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों का एक अभूतपूर्व पुनरुद्धार किया गया। **अतः कथन 3 सही है।**

- निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा संबंधी विषयों का उल्लेख **समवर्ती सूची (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची III)** में किया गया है:

- **विषय नंबर 23:** सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोज़गार और बेरोज़गारी
- **विषय नंबर 24:** कार्य की शर्तों, भविष्य निधि, नियोक्ताओं के दायित्व, श्रमिकों के मुआवज़े, अमान्यता और वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ सहित श्रमिकों का कल्याण। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामले राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों और समवर्ती सूची के विषयों में सूचीबद्ध हैं।

- **अनुच्छेद 41:** काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार।

- **अनुच्छेद 42:** काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। **अतः कथन 1 सही है।**

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एक व्यक्ति, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
2. प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं ही विघटित हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?



- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न ही 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।

- वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को, जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, 6 माह के लिये प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। **अतः कथन 1 सही है।**

- चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, **प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद विघटित होती है, न कि लोकसभा। अतः कथन 2 सही नहीं है।**

- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा विचारों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।

92. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उप-राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- राष्ट्रपति के रूप में वह केवल छह माह तक कार्य कर सकता है।
- इस अवधि के दौरान, वह राज्यसभा के सभापति को देय किसी भी वेतन व भत्ते का अधिकारी नहीं होता है।

- इस अवधि के दौरान, वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्यों का निर्वहन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु, तथा अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद-65)। **कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह केवल छह माह कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। अतः कथन 1 सही है।**

- संविधान में उप-राष्ट्रपति के लिये **भत्तों और परिलब्धियों (Emoluments)** की व्यवस्था नहीं की गई है। उसे जो भी वेतन मिलता है, वह राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है। उप-राष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन व भत्ते नहीं मिलते हैं, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते मिलते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**

- कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि के दौरान, उसके कार्यों का निर्वहन उप-सभापति द्वारा किया जाता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वह स्वायत्त ज़िलों के गठन एवं पुनर्गठन की भी शक्ति रखता है।
- यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए, तो



उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किये गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के अंतर्गत, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। हालाँकि स्वायत्त ज़िलों को गठित और पुनर्गठित करने की शक्ति राज्यपाल के अधीन आती है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किये गए कार्य अवैध नहीं माने जाते हैं तथा वे प्रभावी बने रहते हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

94. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
- मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद-74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है,

जबकि अनुच्छेद-75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ तथा वेतन एवं भत्तों से संबंधित है।

- सरकार की **संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है।** अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। **अतः कथन 1 सही है।**
- 91वें संविधान संशोधन विधेयक, 2003 द्वारा इस उपबंध का समावेश किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। **अतः कथन 2 सही है।**
- मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन मतदाताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और नए चुनाव की मांग कर सकती है। **अतः कथन 3 सही है।**

95. भारतीय संविधान में केंद्र सरकार तीन प्रकार की निधियों की व्यवस्था की गई है। इन निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से प्राधिकृत सभी भुगतान संचित निधि से किये जाते हैं।
- भारत के लोक लेखा में भविष्य निधि जमा, बचत बैंक जमा और प्रेषित धन भी शामिल हैं।
- आकस्मिकता निधि एक सांविधिक निधि है जिसका संचालन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 1
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:



- अनुच्छेद-266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखाओं से संबंधित है।
 - भारत की संचित निधि एक ऐसी निधि है, जिसमें से सभी प्राप्तियाँ जमा की जाती हैं और सभी भुगतान किये जाते हैं। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि में से किये जाएंगे। इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित (निकालना) नहीं किया जा सकता है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - भारत के **लोक लेखा** में भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषित धन आदि शामिल हैं। इस लेखे को **कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित** किया जाता है अर्थात् इस खाते से भुगतान **संसदीय विनियोजन के बिना** किया जा सकता है। **अतः कथन 2 सही है।**
 - संविधान संसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने के लिये अधिकृत करता है। इस प्रकार, संसद ने भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 पारित किया। अतः यह एक सांविधिक निधि है और इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है। निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। **अतः कथन 3 सही है।**
96. निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को अभिव्यक्त कर सकती है?
1. अविश्वास प्रस्ताव पारित करके
 2. धन्यवाद प्रस्ताव पारित न करके
 3. लोकसभा में धन विधेयक अस्वीकृति करके
- नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
- a. केवल 1 और 3
 - b. केवल 1
 - c. केवल 1 और 2
 - d. 1, 2 और 3
- उत्तर: (d)**
व्याख्या:
- संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है, जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, लोकसभा, मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, जिसे **'धन्यवाद प्रस्ताव'** कहा जाता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। इस संबोधन पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है और बहस के बाद इसे मतदान हेतु रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। **अतः कथन 2 सही है।**
 - **संविधान का अनुच्छेद 110** धन विधेयक को परिभाषित करता है। संविधान में धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया उल्लिखित है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं, परंतु इसे विचार के लिये वापस नहीं भेज सकते लोकसभा में अस्वीकृति की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। **अतः कथन 3 सही है।**
97. यूरेनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यूरेनियम को एक प्रमुख खनिज (Major Mineral) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 2. भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- a. केवल 1
 - b. केवल 2
 - c. 1 और 2 दोनों
 - d. न तो 1 और न ही 2
- उत्तर: (c)**
व्याख्या:



- संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के अनुसरण में, संसद ने 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार, यूरेनियम को एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। **अतः कथन 1 सही है।**
- भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले में स्थित तुममालपल्ले की खदान को सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। **अतः कथन 2 सही है।**

98. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 'मार्गदर्शन योजना' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की एक योजना है।
2. वाव शिखर सम्मलेन- 2019, अपशिष्ट प्रबंधन में आय सृजन गतिविधि और उद्यमशीलता को अपनाने हेतु महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 'मार्गदर्शन' अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत बेहतर मान्यता प्राप्त या उच्च प्रदर्शन करने वाले कुछ संस्थानों का चुनाव किया गया है, ताकि वे अपेक्षाकृत नए संस्थानों या ऐसे संस्थानों जिनका प्रदर्शन मापदंडों के अनुरूप नहीं रहा है, को परामर्श दे सकें अथवा उनका मार्गदर्शन कर सकें। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- वाव शिखर सम्मलेन (Waste Management Accelerators for Aspire Women Entrepreneurs Summit-WAVE Summit) युवा महिला छात्राओं के लिये देश का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जहाँ

अपशिष्ट प्रबंधन में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। **अतः कथन 2 सही है।**

- यह समिट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education-AICTE) और भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान (Institute of Waste Management-IIWM) द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।
- AICTE और IIWM द्वारा इच्छुक प्रतिभागियों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें "स्टार्ट अप इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया" से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

99. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM) के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
2. यह प्राकृतिक आपदा के कारण राहत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कैबिनेट सचिवालय में एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee-NCCM) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- इस समिति का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। **अतः कथन 2 सही है।**
- इस समिति में कैबिनेट सचिव और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ-साथ अन्य संगठन भी शामिल हैं।



- NCMC आवश्यकता पड़ने पर संकट प्रबंधन समूह (CMG) को दिशा-निर्देश देता है।

- CMG प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र राहत से संबंधित मामलों से संबंधित है। इस समूह में राहत आयुक्त (अध्यक्ष) और विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के अन्य नोडल अधिकारी शामिल हैं।

100. राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा जारी किया जाता है।
2. यह एक बहुआयामी उपकरण है जो राज्यों को उनके बजट की गुणवत्ता के आधार पर रैंक तय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a. केवल 1
- b. केवल 2
- c. 1 और 2 दोनों
- d. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा विकसित समग्र राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (FPI) केंद्रीय और राज्य स्तरों पर कई संकेतकों का उपयोग करते हुए बजट की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु एक अभिनव उपकरण है। **अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।**
- इस सूचकांक को तैयार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) की मानव विकास सूचकांक प्रक्रिया (Human Development Index Methodology) को अपनाया गया है।
- यह सूचकांक सरकारी बजट की गुणवत्ता के आकलन हेतु छह घटकों पर आधारित है।
 - **राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) की गुणवत्ता।**
 - **पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) की गुणवत्ता।**

- **राजस्व (Revenue) की गुणवत्ता।**
- **राजकोषीय विवेक-I (Fiscal Prudence)-** राजकोषीय घाटा : GDP अनुपात द्वारा आकलन।
- **राजकोषीय विवेक-II (Fiscal Prudence)** राजस्व घाटा : GDP अनुपात द्वारा आकलन।
- **कर्ज सूचकांक (Debt Index) का** GDP के अनुपात में ऋण और गारंटी में परिवर्तन के आधार पर आकलन।

प्रमुख निष्कर्ष:

- CII ने राजकोषीय अनुशासन के पैमाने पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2016-17 की अवधि में गैर-विशेष श्रेणी में शामिल 18 राज्यों का 'राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक' तैयार किया।
 - व्यय की गुणवत्ता के संदर्भ में आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कम आय वाले राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने व्यय में गुणवत्ता लाते हुए हाल के कुछ वर्षों में निरंतर राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक पर शानदार प्रदर्शन किया है।
 - बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कम आय वाले राज्यों जिनका राजकोषीय घाटा उच्च है, का FPI पर प्रदर्शन अच्छा रहा है।